ेविजनेस पोस्ट के अन्तर्गत डाक शुल्क के नगद भुगतान (बिना डाक टिकट) के प्रेषण हेतु अनुमर्त क्रमांक जी. 2-22-छत्तीसगढ़ गजट/38 सि. से. भिलाई, दिनांक 30-5-2001.''



पंजीयन क्रमांक ''छत्तीसगढ़/दुर्ग/ सी. ओ./रायपुर 17/2002. ''

छत्तीसगढ़ राजपत्र

प्राधिकार से प्रकाशित

क्रमांक 51]

रायपुर, शुक्रवार, दिनांक 23 दिसम्बर 2005-पौष 2, शक 1927

विषय—सूची

भाग 1.—(1) राज्य शासन के आदेश, (2) विभाग प्रमुखों के आदेश, (3) उच्च न्यायालय के आदेश और अधिसूचनाएं, (4) राज्य शासन के संकल्प, (5) भारत शासन के आदेश और अधिसूचनाएं, (6) निर्वाचन आयोग, भारत की अधिसूचनाएं,

(7) लोक-भाषा परिशिष्ट.

भाग २.—स्थानीय निकाय की अधिसूचनाएं.

भाग 3.—(1) विज्ञापन और विविध सूचनाएं, (2) सांख्यिकीय सूचनाएं.

भाग 4.—(क) (1) छत्तीसगढ़ विधेयक, (2) प्रवर समिति के प्रतिवेदन, (3) संसद में पुर:स्थापित विधेयक, (ख) (1) अध्यादेश, (2) छत्तीसगढ़ अधिनियम, (3) संसद् के अधिनियम, (ग) (1) प्रारूप नियम, (2) अंतिम नियम.

भाग १

राज्य शासन के आदेश

सामान्य प्रशासन विभाग मंत्रालय, दाऊ कल्याण सिंह भवन, रायपुर

रायपुर, दिनांक 8 दिसम्बर 2005

क्रमांक एफ 9-21/05/1-8.—श्री विनोद गुप्ता, दूरसंचार सेवा (1987 वैच) की सेवाएं, भारतीय दूरसंचार निगम नई दिल्ली ने प्रतिनियुक्ति पर इस विभाग को सोंपने की सहमति के फलस्वरूप श्री विनोद गुप्ता, उप महाप्रबंधक (WTR) भारतीय दूरसंचार निगम लि. रायपुर, को कार्यभार ग्रहण करने के दिनांक से अस्थाई रूप से आगामी आदेश तक संयुक्त सचिव, छत्तीसगढ़ शासन वाणिज्य एवं उद्योग विभाग पदस्थ किया जाता है.

इनकी प्रतिनियुक्ति की सेवा शर्ते बाद में जारी की जावेगी.

रायपुर, दिनांक 8 दिसम्बर 2005

क्रमांक एफ़ 9-21/05/1-8.—श्री अनूप श्रीवास्तव, (भा.व.से.) विशेष सचिव, छत्तीसगढ़ शासन, वाणिज्य एवं उद्योग विभाग को तत्काल प्रभाव से अस्थाई रूप से आगामी आदेश तक विशेष सचिव, छत्तीसगढ़ शासन, कृषि, पशुपातन एवं मछली पालन विभाग, पदस्थ किया जाता है. श्री अनूप श्रीवास्तव को उनके कर्त्तव्यों के साथ-साथ संचालक, पशुपालन, छत्तीसगढ़ रायपुर का अतिरिक्त प्रभार भी सौंपा जाता है.

2. श्री अनूप श्रीवास्तव द्वारा संचालक, पशुपालन के पद का कार्यभार ग्रहण करने पर श्री एच. एल. प्रजापित, संचालक, पशुपालन के प्रभार से मुक्त होंगे.

छत्तीसगढ़ के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार, आर.-पी. बगाई, मुख्य सचिव.

्र फोर कि अन्तर्भक्त कि विक्रिया का आकर र आस्प । सं

रायपुर, दिनांक 9 दिसम्बरं 2005

क्रमांक एफ 1-2/2005/1/5.—राज्य शासन एतद्द्वारा संलग्न परिशिष्ट "क" में दर्शाये गये नगरीय निकायों में नियत मतदान दिनांक 16 दिसम्बर, 2005 वार शुक्रवार को केवल नगरीय निकाय (नगर पालिक निगम एवं नगर पालिका परिषद्) क्षेत्रों के लिये सामान्य अवकाश घोषित करता है.

2. उक्त दिनांक को केवल ऊपर उल्लेखित संबंधित क्षेत्रों के लिये परक्राम्य लिखित अधिनियम-1881 (निगोशिएबल) इन्स्ट्रूमेंट एक्ट-1881) के क्रमांक-26 की धारा-25 के अन्तर्गत सार्वजनिक अवकाश भी घोषित करता है.

> छत्तीसगढ़ के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार, पंकज द्विवेदी, प्रमुख सचिव

> > परिशिष्ट-''क''

नगरपालिका आम निर्वाचन वर्ष 2005 नगरीय निकायों की सूची

क्र. (1)	জিলা (2)	नगरीय निकाय का कोड (3)	नगरपालिका का नाम (4)	.वार्डों की संख्या (5)
1.	दुर्ग	110402 110404 110407	नगरपालिक निगम, भिलाई नगरपालिका परिषद् भिलाई चरौदा नगरपालिका परिषद् जामुल	,67 36 18
			योग	121

रायपुर, दिनांक 01 दिसम्बर 2005

क्रमांक एफ 7-15/2005/1/6.—राज्य शासन ने, सूचना का अधिकार अधिनयम, 2005 की धारा 15(1) अनुसार, दिनांक 01 अक्टूबर, 2005 को ''छत्तीसगढ़ राज्य सूचना आयोग'' का गठन किया है. अधिनियम की धारा 15 (7) अनुसार एतट्द्वारा ''छत्तीसगढ़ राज्य सूचना आयोग'' का मुख्यालय रायपुर धोषित करता है.

छत्तीसगढ़ के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार, नन्द कुमार, सचिव.

रायपुर, दिनांक 5 दिसम्बर 2005

क्रमांक ई-7/23/2004/1/2.—श्री एस. के. कुंजूर, सचिव, छत्तीसगढ़ शासन, महिला एवं बाल विकास तथा समाज कल्याण विभाग को दिनांक 24-12-2005 से 31-12-2005 तक (08 दिवस) का अर्जित अवकाश स्वीकृत किया जाता है. साथ ही दिनांक 01-01-2006 के शासकीय अवकाश को जोड़ने की अनुमित भी दी जाती है.

- 2. अवकाश से लौटने पर श्री कुजूर, भा. प्र. से. आगामी आदेश तक सचिव, छत्तीसगढ़ शासन, महिला एवं बाल विकास तथा समाज कल्याण विभाग के पद पर पुन: पदस्थ होंगे.
- 3. अवकाश काल में श्री कुजूर, भा.प्र.से. को अवकाश वेतन भत्ता एवं अन्य भत्ते उसी प्रकार देय होंगे, जो उन्हें अवकाश पर जाने के पूर्व मिलते थे.
- प्रमाणित किया जाता है कि यदि श्री कुजूर, भा. प्र. से. अवकाश पर नहीं जाते तो अपने पद पर कार्य करते रहते.

रायपुर, दिनांक 6 दिसम्बर 2005

क्रमांक ई-7/19/2004/1/2.—इस विभाग के समसंख्यक आदेश दिनांक 28-11-2005 द्वारा श्री सी. के. खेतान, भा.प्र.से., सचिव, छत्तीसगढ़ शासन, जन सम्पर्क विभाग को दिनांक 05-12-2005 से 09-12-2005 तक (05 दिवस) का अर्जित अवकाश स्वोकृत किया गया था, एतद्द्वारा निरस्त किया जाता है.

रायपुर, दिनांक 7 दिसम्बर 2005

क्रमांक ई-7/13/2003/1/2. — श्री एम. एस. धुर्वे, भा.प्र.से., जो आयुक्त, भू-अभिलेख, छ.ग., रायपुर के पद पर पदस्थ थे तथा जिनका दिनांक 19-11-2005 को देहावसान हो गया है, को दिनांक 24-01-2005 से 10-07-2005 तक (169 दिवस) का लघुकृत अवकाश तथा दिनांक 11-07-2005 से 18-11-2005 तक (130 दिवस) का अर्जित अवकाश स्वीकृत किया जाता है.

2. अवकाश काल में श्री धुर्वे, भा.प्र.से. को अवकाश वेतन भत्ता एवं अन्य भत्ते उसी प्रकार देय होंगे, जो उन्हें उक्त अवका : के पूर्व मिलते थे

रायपुर, दिनांक 7 दिसम्बर 2005

क्रमांक ई-7/21/2004/1/2.—श्री अजय सिंह, भा.प्र.से., सिचव, छत्तीसगढ़ शासन, नगरीय विकास विभाग को दिनांक 25-11-2005 एवं 26-11-2005 तक (दो दिवस) का अर्जित अवकाश स्वीकृत किया जाता है. साथ ही दिनांक 27 नवम्बर, 2005 के शासकीय अवकाश को जोड़ने की अनुमति भी दी जाती है.

- 2. अवकाश से लौटने पर श्री सिंह, भा. प्र. से. आगामी आदेश तक सचिव, छत्तीसगढ़ शासन, नगरीय विकास विभाग के पद पर पुन: पदस्थ होंगे.
- 3. अवकाश काल में श्री सिंह, भा.प्र.से. को अवकाश वेतन भत्ता एवं अन्य भत्ते उसी प्रकार देय होंगे, जो उन्हें अवकाश पर जाने के पूर्व मिलते थे.
- प्रमाणित किया जाता है कि यदि श्री सिंह, भा. प्र. से. अवकाश पर नहीं जाते तो अपने पद पर कार्य करते रहते.

छत्तीसगढ़ के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार, के. के. खाजपेयी, अवर सचिव.

रायपुर, दिनांक 9 दिसम्बर 2005

अधिसूचना/संशोधन

क्रमांक एफ-7/15/2005/1/6.—इस विभाग की अधिसूचना क्रमांक एफ 7-15/2005/1/6 दिनांक 26 नवम्बर, 05 में शब्द समूह ''नवनियुक्त राज्य सूचना आयुक्त'' के स्थान पर शब्द समूह ''नवनियुक्त राज्य मुख्य सूचना आयुक्त'' प्रतिस्थिापित किया जाता है.

> छत्तीसगढ़ के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार, एस. आर. सेजकर, अवर सचिव.

कृषि विभाग मंत्रालय, दाऊ कल्याण सिंह भवन, रायपुर

रायपुर, दिनांक 7 दिसम्बर 2005

क्रमांक/4183/सी.एम.घोषणा/6/04-05/14-3.—छत्तीसगढ़ कृषि उपज मण्डी अधिनियम 1972 (क्र. 24 सन् 1973) की धारा 60 द्वारी प्रदत्त शक्तियों को प्रयोग में लाते हुए, राज्य सरकार, एतद्द्वारा, उक्त अधिनियम की अनुसूची में निम्नलिखित संशोधन करती है जिसके लिये उक्त अधिनियम की धारा 60 द्वारा अपेक्षित किये अनुसार पूर्व में प्रकाशित की जा चुकी है, अर्थात् :—

संशोधन

_उक्त_अनुसूची ॒में,—

^{&#}x27;कृषि उपज की अनुसूची'' में मद बारह के अनुक्रमांक 2 में ''हर्रा'' एवं अनुक्रमांक 6 ''गोंद'' (सब प्रकार का) लोप-किया जाय.

No./4183/C.M. Dec/6/04-05/14-3.—In exercise of the powers conferred by Section 60 of the Chhattisgarh Krishi Upaj Mandi Adhiniyam, 1972 (No. 24 of 1973), the State Government hereby makes the following amendments in the schedule of the said Act, the same having been previously published as required under Section 60 of the Act, namely;—

AMENDMENT

In the said Schedule,-

In serial number 2 "Harra" and Serial number 6 "Gond" (of All Categories) of the item Twelve in the "Schedule of Agricultural produce" shall be omitted.

छत्तीसगढ़ के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार, प्रताप कृदत्त, उप-सचिव.

राजस्व विभाग

कार्यालय, कलेक्टर, जिला राजनांदगांव, छत्तीसगढ़ एवं पदेन उप-सचिव, छत्तीसगढ़ शासन, राजस्व विभाग

राजनांदगांव, दिनांक ९ दिसम्बर 2005

क्रमांक 11006/भू-अर्जन/2004. — चूंकि राज्य शासन को यह प्रतीत होता है कि इससे संलग्न अनुसूची के खाने (1) से (4) में वर्णित भूमि की अनुसूची के खाने (6) में उसके सामने दिये गये सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है, अथवा आवश्यकता एड़ने की संभावना है. अतः भू-अर्जन अधिनियम, 1984 (क्रमांक 1 सन् 1894) की धारा 4 को उपधारा (1) के उपबन्धों के अनुसार सभी संबंधित व्यक्तियों को इसके द्वारा इस आशय की सूचना दी जाती है कि राज्य शासन, इसके द्वारा, अनुसूची के खाने (5) में उल्लेखित अधिकारी को उक्त भूमि के संबंध में उक्त धारा 4 की उपधारा (2) द्वारा दी गई शक्तियों का प्रयोग करने के लिए प्राधिकृत करता है:—

अनुसूची

भूमि का वर्णन				धारा 4 की उपधारा (2)	सार्वजनिक प्रयोजन 🕝
जिला	तहसील	नगर∕ग्राम	लगभग क्षेत्रफल (हेक्टेयर में)	के द्वारा प्राधिकृत अधिकारी	का वर्णन
(1)	(2)	. (3)	(4)	(5)	(6)
राजनांदगांव	डोंगरगांव	कोहका प.ह.नं. 16	2.826	कार्यपालन अभियंता, मोंगरा परियोजना, जल संसाधन संभाग, डोंगरगांव	मोंगरा बॅराज परियोजना के कोहका लघु नहर निर्माण के लिए है.

भूमि का नक्शा (प्लान) का निरीक्षण भू-अर्जन अधिकारी (मोंगरा बॅराज परियोजना), जिला कार्यालय राजनांदगांव में किया जा सकता है.

राजनांदगांव, दिनांक १ दिसम्बर 2005

क्रमांक 11007/भू-अर्जन/2004.—चूंकि राज्य शासन को यह प्रतीत होता है कि इससे संलग्न अनुसूची के खाने (1) से (4) में वर्णित भूमि की अनुसूची के खाने (6) में उसके सामने दिये गये सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है, अथवा आवश्यकता पड़ने की संभावना है. अतः भू-अर्जन अधिनियम, 1984 (क्रमांक 1 सन् 1894) की धारा 4 की उपधारा (1) के उपबन्धों के अनुसार सभी संबंधित व्यक्तियों को इसके द्वारा इस आशय की सूचना दी जाती है कि राज्य शासन, इसके द्वारा, अनुसूची के खाने (5) में उद्योखित अधिकारी को उक्त भूमि के संबंध में उक्त धारा 4 की उपधारा (2) द्वारा दी गई शक्तियों का प्रयोग करने के लिए प्राधिकृत करता है :—

अनुसूची

भूमि का वर्णन				धारा ४ की उपधारा (2)	सार्वजनिक प्रयोजन
जिला	तहसील	नग्र/ग्रोम	लगभग क्षेत्रफल (हेक्टेयर में)	के द्वारा प्राधिकृत अधिकारी	का वर्णन
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
राजनांदगांव २५४ <i>हा</i> ग्रे ४१४	राजनांदगांव : १५६४:१७६ (१७.	अछोली प.हि.नें. 60 ^{(18)पन} ्	5.442 দি সংখ্যান	कार्यपालन अभियंता, मोंगरा परियोजना, जल संसाधनी संभाग, डोंगरगांव.	मोंगरा बॅराज परियोजना के अछीली लघु नहर निर्माण के लिए है.

भूमि का नक्शा (प्लान) का निरीक्षण भू-अर्जन अधिकारी (मोंगरा बॅराज परियोजना), जिला कार्यालय राजनांदगांव में किया जा सकता है.

राजनांदगांव, दिनांक 13 दिसम्बर 2005

क्रमांक 11056/भू-अर्जन/05.— चूंकि राज्य शासन को यह प्रतीत होता है कि इससे संलग्न अनुसूची के खाने (1) से (4) में वर्णित भूमि की अनुसूची के खाने (6) में उसके सामने दिये गये सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है, अथवा आवश्यकता पड़ने की संभावना है. अत: भू- अर्जन अधिनियम, 1894 (क्रमांक 1 सन् 1894) की धारा 4 की उपधारा (1) के उपबन्धों के अनुसार सभी संबंधित व्यक्तियों को इसके द्वारा इस आशय की सूचना दी जाती है कि राज्य शासन, इसके द्वारा, अनुसूची के खाने (5) में उल्लेखित अधिकारी को उक्त भूमि के संबंध में उक्त धारा 4 की उपधारा (2) द्वारा दी गई शक्तियों का प्रयोग करने के लिए प्राधिकृत करता है :—

अनुसूची

भूमि का वर्णन				धारा ४ की उपधारा (2)	सार्वजनिक प्रयोजन
जिला .	तहसील	नगर/ग्रॉम	लगभग क्षेत्रफल (हेक्टेयर में)	के द्वारा प्राधिकृत अधिकारी	का वर्णन
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
राजनांदगांव	डोंगरगांव	मोहड़ प.ह.नं. 16	7.946	कार्यपालन अभियंता, मोंगरा परियोजना, जल संसाधन संभाग, डोंगरगांव	मोंगरा बॅराज परियोजना के मोहड़ लघु नहर निर्माण के लिए है.

भूमि का नंक्शा (प्लान) का निरीक्षण भू-अर्जन अधिकारी (मोंगरा बॅराज परियोजना), जिला कार्यालय राजनांदगांव में किया जा सकता है.

छत्तीसगढ़ के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार, जी. एस. मिश्रा, कलेक्टर एवं पदेन उप-सचिव.

कार्यालय, कलेक्टर, जिला दुर्ग, छत्तीसगढ़ एवं पदेन उप-सचिव, छत्तीसगढ़ शासन, राजस्व विभाग

दुर्ग, दिनांक 6 दिसम्बर 2005

क्रमांक 1589/प्र.-1/भू-अर्जन/अ.वि.अ./20.—चूंकि राज्य शासन को यह प्रतीत होता है कि इससे संलग्न अनुसूची के खाने (1) से (4) में विर्णित भूमि की अनुसूची के खाने (6) में उसके सामने दिये गये सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है, अथवा आवश्यकता एड़ने की संभावना है. अत: भू-अर्जन निर्धिनयम, 1894 (क्रमांक एक सन् 1894) की धारा 4 की उपधारा (1) के उपबन्धों के अनुसार सभी संबंधित व्यक्तियों को इसके द्वारा इस आः की सूचना दी जाती है कि राज्य शासन, इसके द्वारा, अनुसूची के खाने (5) में उल्लेखित अधिकारी को उक्त भूमि के संबंध में उक्त धारा 4 की उपधारा (2) द्वारा दी गई शक्तियों का प्रयोग करने के लिए प्राधिकृत करता है:—

अनुसूची

भूमि का वर्णन				धारा ४ की उपधारा (2)	सार्वजनिक प्रयोजन
जिला	तहसील	नगर/ग्राम	लगभग क्षेत्रफल (हेक्टेयर में)	के द्वारा प्राधिकृत अधिकारी	का वर्णन
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
ुदुर्ग ,	धम्धा म }ः ज्यस्ट	रौता _{ः अस्तर्भ}	3.36	कार्यपालन अभियंता, तांदुला जल संसाधन संभाग, दुर्ग छ.ग.	रौता जलाशय बांध एवं नहर हेतु भूमि अर्जन

भूमि का नक्शा (प्लान) अनुविभागीय अधिकारी (राजस्व), दुर्ग के कार्यालय में देखा जा सकता है.

दुर्ग, दिनांक 6 दिसम्बर 2005

क्रमांक 1592/प्र.-1/भू-अर्जन/अ.वि.अ./20.—चूंकि राज्य शासन को यह प्रतीत होता है कि इससे संलग्न अनुसूची के खाने (1) से (4) में विर्णत भूमि की अनुसूची के खाने (6) में उसके सामने दिये गये सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है, अथवा आवश्यकता एड़ने की संभावना है. अत: भू-अर्जन अधिनियम, 1894 (क्रमांक एक सन् 1894) की धारा 4 की उपधारा (1) के उपबन्धों के अनुसार सभी संबंधित व्यक्तियों को इसके द्वारा इस आशय की सूचना दी जाती है कि राज्य शासन, इसके द्वारा, अनुसूची के खाने (5) में उल्लेखित अधिकारी को उक्त भूमि के संबंध में उक्त धारा 4 की उपधारा (2) द्वारा दी गई शक्तियों का प्रयोग करने के लिए प्राधिकृत करता है:—

अनुसूची

भूमि का वर्णन				धारा 4 की उपधारा (2)	सार्वजनिक प्रयोजन
जिला	तहसील	नगर∕ग्राम	लगभग क्षेत्रफल (हेक्टेयर में)	के द्वारा प्राधिकृत अधिकारी	- का वर्णन
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
दुर्ग	- धमधा	बिरेझर	2.23	कार्यपालन अभियंता, तांदुला जल संसाधन संभाग, दुर्ग छ.ग.	रौता जलाशय बांध एवं नहर हेतु भूमि अर्जन.

भूमि का नक्शा (प्लान) अनुविभागीय अधिकारी (राजस्व), दुर्ग के कार्यालय में देखा जा सकता है.

छत्तीसगढ़ के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार, जबाहर श्रीवास्तव, कलेक्टर एवं पदेन उप-सचिव.

कार्यालय, कलेक्टर, जिला रायपुर, छत्तीसगढ़ एवं पदेन सचिव, छत्तीसगढ़ शासन, राजस्व विभाग

रायपुर, दिनांक 20 जुलाई 2005

क्रमांक-क/भू-अर्जन/ 8 अ/82 वर्ष 2004-05. — चूंकि राज्य शासन को यह प्रतीत होता है कि इससे संलग्न अनुसूची के खाने (1) से (4) में वर्णित भूमि की अनुसूची के खाने (6) में उसके सामने दिये गये सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है, अथवा आवश्यकता पड़ने की संभावना है. अत: भू-अर्जन अधिनियम, 1894 (क्रमांक 1 सन् 1894) की धारा 4 की उपधारा (1) के उपबन्धों के अनुसार इसके द्वारा सभी संबंधित व्यक्तियों को इस आशय की सूचना दी जाती है कि राज्य शासन, इसके द्वारा, इस अनुसूची के खाने (5) में उल्लेखित अधिकारी को उक्त भूमि के संबंध में उक्त धारा 4 की उपधारा (2) द्वारा दी गई शक्तियों का प्रयोग करने के लिए प्राधिकृत करता है :—

अनुसूची

भूमि का वर्णन				धारा ४ की उपधारा (2)	सार्वजनिक प्रयोजन
জিল <u>া</u>	तहसील	नगर/ग्राम	लगभग क्षेत्रफल (हेक्टेयर में) -	के द्वारा प्राधिकृत अधिकारी	का वर्णन
(1)	(2.)	(3)	(4)	(5)	(6)
रायपुर	भाटापारा	रामपुर प. ह. नं. 17/35	0.372	कार्यपालन अभियंता, म. ज. प., डिसनेट संभाग क्र. 3, तिल्दा.	लालपुर उपनहर निर्माण हेतु

रायपुर, दिनांक 20 जुलाई 2005

क्रमांक-क/भू-अर्जन/ 21 अ/82 वर्ष 04-05.—चूंकि राज्य शासन को यह प्रतीत होता है कि इससे संलग्न अनुसूची के खाने (1) से (4) में वर्णित भूमि की अनुसूची के खाने (6) में उसके सामने दिये गये सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है, अथवा आवश्यकता पड़ने की संभावना है. अत: भू-अर्जन अधिनियम, 1894 (क्रमांक 1 सन् 1894) की धारा 4 की उपधारा (1) के उपबन्धों के अनुसार इसके द्वारा सभी संबंधित व्यक्तियों को इस आशय की सूचना दी जाती है कि राज्य शासन, इसके द्वारा, इस अनुसूची के खाने (5) में उल्लेखित अधिकारी को उक्त भूमि के संबंध में उक्त धारा 4 की उपधारा (2) द्वारा दी गई शक्तियों का प्रयोग करने के लिए प्राधिकृत करता है :—

भूमिं का व	त्रर्णन	धारा ४ की उपधारा (2)	सार्वजनिक प्रयोजन
जिला , तहसील नगर	ग्राम लगभग क्षेत्रफल	ं के द्वारा	का वर्णन
	(हेक्टेयर में)	, प्राधिकृत अधिकारी	· <u>·</u> ·
(1) (2) (3	3) (4)	(5)	(6)
रायपुर ः सिम्गा 🔧 ुखिल	<u> </u>	कार्यपालन अभियंता, म. ज. प.	, , केसली माइनर नहर निर्माण
ч. ह	i.=21= <u>-2.5.</u>	डिसनेट संभाग क्र. 3, तिल्दा.	हेतु.

रायपुर, दिनांक २१ जुलाई 2005

क्रमांक-क/भू-अर्जन/ 4 अ/82 वर्ष 04-05.—चूंकि राज्य शासन को यह प्रतीत होता है कि इससे संलग्न अनुसृची के खाने (1) में (4) में विर्णित भूमि की अनुसूची के खाने (6) में उसके सामने दिये गये सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है, अथवा आवश्यकता पड़ने को संभावना है. अत: भू-अर्जन अधिनियम, 1894 (क्रमांक 1 सन् 1894) की धारा 4 की उपधारा (1) के उपवन्धों के अनुसार इसके द्वारा सभी संबंधित व्यक्तियों को इस आशय को सूचना दी जाती है कि राज्य शासन, इसके द्वारा, इस अनुसूची के खाने (5) में उद्घेखित अधिकारी को उक्त भूमि क संबंध में उक्त धारा 4 की उपधारा (2) द्वारा दी गई शक्तियों का प्रयोग करने के लिए प्राधिकृत करता है:—

अनुसृची

भूमि का-वर्णन				धारा ४ की उपधारा (2)	सार्वजनिक प्रयोजन
जिला '	तहसील	नगर/ग्राम	लगभग क्षेत्रफल • (हेक्टेयर में)	के द्वारा प्राधिकृत अधिकारी	का वर्णन
(1)	(2)	(3)	(4)	. (5)	(6)
रायपुर	भाटापारा	. पाटन ⁻ प. ह. नं. 20/38	0.744	कार्यपालन अभियंता, म. ज. प., डिसनेट संभाग क्र. 3, तिल्दा.	चिचपोल माइनर नहर निर्माण हेतु.

रायपुर, दिनांक 29 जुलाई 2005

क्रमांक-क/भू-अर्जन/ 9 अ/82 वर्ष 04-05.—चूंकि राज्य शासन को यह प्रतीत होता है कि इससे संलग्न अनुसूची के खाने (1) से (4) मं वर्णित भूमि की अनुसूची के खाने (6) में उसके सामने दिये गये सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है, अथवा आवश्यकता पड़ने की संभावना है. अत: भू-अर्जन अधिनियम, 1894 (क्रमांक 1 सन् 1894) की धारा 4 की उपधारा (1) के उपबन्धों के अनुसार इसके द्वारा सभी संबंधित व्यक्तियों को इस आशय की सूचना दी जाती है कि राज्य शासन, इसके द्वारा, इस अनुसूची के खाने (5) में उल्लेखित अधिकारी को उक्त भूमि के संबंध में उक्त धारा 4 की उपधारा (2) द्वारा दी गई शक्तियों का प्रयोग करने के लिए प्राधिकृत करता है :—

	9	भूमि का वर्णन		धारा 4 की उपधारा (2)	सार्वजनिक प्रयोजन
जিলা	तहसील	नगर/ग्राम	लगभग क्षेत्रफल (हेक्टेयर में)	के द्वारा प्राधिकृत अधिकारी	का वर्णन
(1) ·	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
रायपुर	भाटापारा	हसदा प. ह. नं. 11/40	3.140	कार्यपालन अभियंता, म. ज. प., डिसनेट संभाग क्र. 3, तिल्दा.	हसदा माईनर नहर निर्माण हेतु.

रायपुर, दिनांक 29 जुलाई 2005

क्रमांक-क/भू-अर्जन/ 16 अ/82 वर्ष 04-05.—चूंकि राज्य शासन को यह प्रतीत होता है कि इससे संलग्न अनुसूची के खाने (1) से (4) में वर्णित भूमि को अनुसूची के खाने (6) में उसके सामने दिये गयें सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है, अथवा आवश्यकता पड़ने की संभावना है. अत: भू-अर्जन अधिनियम, 1894 (क्रमांक 1 सन् 1894) की धारा 4 की उपधारा (1) के उपबन्धों के अनुसार इसके द्वारा सभी संबंधित व्यक्तियां को इस आशय की सूचना दी जाती है कि राज्य शासन, इसके द्वारा, इस अनुसूची के खाने (5) में उल्लेखित अधिकारी को उक्त भूमि के संबंध में उक्त धारा 4 की उपधारा (2) द्वारा दी गई शक्तियों का प्रयोग करने के लिए प्राधिकृत करता है :—

अनुसूची

		भूमि का वर्णन		धारा ४ की उपधारा (.2)	सार्वजनिक प्रयोजन
जिला	तहसील	नगर∕ग्राम	लगभग क्षेत्रफल (हेक्टेयर में)	ें के द्वारा प्राधिकृत अधिकारी	का वर्णन
(1)	(2)	(3)	(4)	(5) ·	(6)
.रायपुर	भाटापारा	बिज् राडीह प. ह. नं. 5/41	1.526- ₇₋₁₆	ः कार्यपालन अभियंता, म _{्रा} जः,प _{ःह} ः डिसनेट संभाग क्र. ३, तिल्दा.	ः : बिजराडीह वितरक नहर निर्माण हेतु.

रायपुर, दिनांक 22 अक्टूबर 2005

क्रमांक/क/वा./भू. वि.अ./प्र. क्र. 39-अ/82 वर्ष 2004-05. — चूंकि राज्य शासन को यह प्रतीत होता है कि इससे संलग्न अनुसूची के खाने (1) से (4) में वर्णित भूमि की अनुसूची के खाने (6) में उसके सामने दिये गये सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है, अथवा आवश्यकता पड़न की संभावना है. अत: भू-अर्जन अधिनियम, 1894 (क्रमांक 1 सन् 1894) की धारा 4 की उपधारा (1) के उपबन्धों के अनुसार इसके द्वारा सभी संबंधित व्यक्तियों को इस आशय की सूचना दी जाती है कि राज्य शासन, इसके द्वारा, इस अनुसूची के खाने (5) में उल्लेखित अधिकारी को उक्त भूमि के संबंध में उक्त धारा 4 की उपधारा (2) द्वारा दी गई शक्तियों का प्रयोग करने के लिए प्राधिकृत करता है :—

भूमि का वर्णन				धारा ४ की उपधारा (2)		सार्वजनिक प्रयोजन	
जिला	तहसील . * :	नगर/ग्राम	लगभग क्षेत्रफल (हेक्टेयर में)	के द्वारा प्राधिकृत अधिक	हार ी	का वर्णन	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)		(6)	
रायपुर	तिल्दा	किरना प. ह. नं. 10	2.650	कार्यपालन अभियंता, जलाशय भारियोजना, संभाग क्र. 3, तिल्दा			

रायपुर, दिनांक 22 अंक्टूबर 2005

क्रमांक/क/वा./भू वि.अ./प्र. क्र. 42-अ/82 वर्ष 2004-05.— चूंकि राज्य शासन को यह प्रतीत होता है कि इससे संलग्न अनुसूची के खाने (1) से (4) में वर्णित भूमि की अनुसूची के खाने (6) में उसके सामने दिये गये सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है, अथवा आवश्यकता पड़ने को संभावना है. अत: भू-अर्जन अधिनियम, 1894 (क्रमांक 1 सन् 1894) की धारा 4 की उपधारा (1) के उपबन्धों के अनुसार इसके द्वारा सभी संबंधित व्यक्तियों को इस आशय की सूचना दी जाती है कि राज्य शासन, इसके द्वारा, इस अनुसूची के खाने (5) में उल्लेखित अधिकारी को उक्त भूमि के संबंध में उक्त धारा 4 की उपधारा (2) द्वारा दी गई शक्तियों का प्रयोग करने के लिए प्राधिकृत करता है :—

अनुसूची

	9	भूमि का वर्णन		धारा ४ की उपधारा (2)	सार्वजनिक प्रयोजन	
जिला तहसील नगर/ग्राम लगभग क्षेत्रफल (हेक्टेयर में)		के द्वारा ' प्राधिकृत अधिकारी	का वर्णन			
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	
रायपुर ंस्क्री	तिल्दा कार्य १ क्षेप्रकार	किरना प. ह.'नं. 10 [*]	1.618 असम्बद्धाः अस्य अस्य	कार्यपालन अभियंता, महानदी जलाशय परियोजना, डिसनेट संभाग क्र. 3, तिल्दा.	किरना वितरक नहर के किरना मोईनर नं. (1) के नहर निर्माण हेतु भू-अर्जन.	

रायपुर, दिनांक 22 अक्टूबर 2005

क्रमांक/क/वा./भू.वि.अ./प्र. क्र. 43-अ/82 वर्ष 2004-05.—चूंकि राज्य शासन को यह प्रतीत होता है कि इससे संलग्न अनुसूची के खाने (1) से (4) में वर्णित भूमि की अनुसूची के खाने (6) में उसके सामने दिये गये सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है, अथवा आवश्यकता पड़ने की संभावना है. अतः भू-अर्जन अधिनियम, 1894 (क्रमांक 1 सन् 1894) की धारा 4 की उपधारा (1) के उपबन्धों के अनुसार इसके द्वारा सभी संबंधित व्यक्तियों को इस आशय की सूचना दी जाती है कि राज्य शासन, इसके द्वारा, इस अनुसूची के खाने (5) में उल्लेखित अधिकारी को उक्त भूमि के संबंध में उक्त धारा 4 की उपधारा (2) द्वारा दी गई शक्तियों का प्रयोग करने के लिए प्राधिकृत करता है :—

अनुसूची

		भूमि का वर्णन		धारा ४ की उपधारा (2)	सार्वजनिक प्रयोजन
जिला	तहसील	नगर/ग्राम	लगभग क्षेत्रफल (एकड़ में)	के द्वारा प्राधिकृत अधिकारी	का वर्णन
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
रायपुर	तिल्दा	़ देवगांव प. ह. नं. 31	2.41	कार्यपालन अभियंता, जलाशय परियोजना, डिसनेट संभाग क्र. 3, तिल्दा (तुलसी) रायपुर (छ.ग.)	मढ़ी वितरक नहर हेतु अर्जित की जा रही भूमि अर्जन.ं ः.

छत्तीसगढ़ के राज्यपाल के नाम से तथा आदेः नुसार, आर. पी. मण्डल, कलेक्टर एवं ५३न सचिव.

कार्यालय, कलेक्टर, जिला कबीरधाम, छत्तीसगढ़ एवं पदेन उप-सचिव, छत्तीसगढ़ शासन, राजस्व विभाग

कबोरधाम, दिनांक ३० नवम्बर २००५

प्र. क्र. 4 अ-82/05-06.— चूंकि राज्य शासन को यह प्रतीत होता है कि इससे संलग्न अनुसूची के खाने (1) सं (4) में वर्णित भूमि की अनुसूची के खाने (6) में उसके सामन दिये गये सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है, अथवा आवश्यकता पड़ने की संभावना है. अत: भू-अर्जन अधिनियम, 1894 (क्रमांक 1 सन् 1894) की धारा 4 की उपधारा (1) के उपबन्धों के अनुसार सभी संबंधित व्यक्तियों को इसके द्वारा इस आशय की सूचना दी जाती है कि राज्य शासन, इसके द्वारा, अनुसूची के खाने (5) में उल्लेखित अधिकारी को उक्त भूमि के संबंध में उक्त धारा 4 की उपधारा (2) द्वारा दी गई शक्तियों का प्रयोग करने के लिए प्राधिकृत करता है :—

अनुसूची

		9	र्मि का वर्णन. 🔭	•	धारा ४ की उपधारा (2)	सार्वजनिक प्रयोजन	
•	जिला	तहसील	नगर∕ग्राम	लंगभग क्षेत्रफल (हेक्टेयर में)	ं के द्वारा प्राधिकृत अधिकारी	का वर्णन	
	(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	
कबीरधाम		कवर्धा	मोहगांव	3.926	कार्यपालन अभियंता सुतियापाट परियोजना संभाग, स/लोहारा जिला-कबीरधाम (छ.ग.)	सुतियापाट परियोजना के अंतर्गत खैरबना शाखा नहर निर्माण हेतु.	

भूमि का नक्शा (प्लान) का अनुविभागीय अधिकारी राजस्व, कवर्धा के न्यायालय में निरीक्षण किया जा सकता है.

कबीरधाम, दिनांक 30 नवम्बर 2005

प्र. क्र. 5 अ-82/05-06. — चूंकि राज्य शासन को यह प्रतीत होता है कि इससे संलग्न अनुसूची के खाने (1) से (4) में वर्णित भूमि की अनुसूची के खाने (6) में उसके सामने दिये गये सार्वजिनक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है, अथवा आवश्यकता पड़ने की संभावना है. अत: भू-अर्जन अधिनियम, 1894 (क्रमांक 1 सन् 1894) की धारा 4 की उपधारा (1) के उपबन्धों के अनुसार सभी संबंधित व्यक्तियों को इसके द्वारा इस आशय की सूचना दी जाती है कि राज्य शासन, इसके द्वारा, अनुसूची के खाने (5) में उल्लेखित अधिकारी को उक्त भूमि के संबंध में उक्त धारा 4 की उपधारा (2) द्वारा दी गई शक्तियों का प्रयोग करने के लिए प्राधिकृत करता है :—

अनुसूची

		भूमि का वर्णन		धारा ४ की उपधारा (2)	सार्वजनिक प्रयोजन
<u> </u> जिला	तहसील	ं नगर/ग्राम	लगभग क्षेत्रफल (हेक्टेयर में)	के द्वारा - प्राधिकृत अधिकारी	का वर्णन
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
कबीरधाम	कवर्धा	बनखैरा	18.525	कार्यपालन अभियंता सुतियापाट परियोजना संभाग, स/लोहारा जिला–कबीरधाम (छ.ग.)	सुतियापाट परियोजना के अंतर्गत उलट नहर नाली हेतु.

भूमि का नक्शा (प्लान) का अनुविभागीय अधिकारी राजस्व, कवर्धा के न्यायालय में निरीक्षण किया जा सकता है.

छतींसगढ़ के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार, बी. एल. तिवारी, कलेक्टर एवं पदेन उप-सचिव.

कार्यालय, कलेक्टर, जिला बिलासपुर, छत्तीसगढ़ एवं पदेन उप-सचिव, छत्तीसगढ़ शासन, राजस्व विभाग

विलासपुर, दिनांक 25 नवम्बर 2005

क्रमांक 1 अ-82/2005-2006. — चूंकि राज्य शासन को यह प्रतीत होता है कि इससे संलग्न अनुसूची के खाने (1) से (4) में वर्णित भूमि की अनुसूची के खाने (6) में उसके सामने दिये गये सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है, अथवा आवश्यकता पड़ने की संभावना है. अतः भू-अर्जन अधिनियम, 1894 (क्रमांक 1 सन् 1894) संशोधित भू-अर्जन अधिनियम, 1984 की धारा 4 की उपधारा (1) के उपबन्धों के अनुसार सभी संबंधित व्यक्तियों को इसके द्वारा इस आशय की सूचना दो जाती है कि राज्य शासन, इसके द्वारा, अनुसूची के खाने (5) में उद्घेखित अधिकारी को उक्त भूमि के संबंध में उक्त धारा 4 की उपधारा (2) द्वारा दी गई शक्तियों का प्रयोग करने के लिए प्राधिकृत करता है:—

अनुसूची

	भूरि	म का वर्णन		धारा ४ की उपधारा (2)	सार्वजनिक प्रयोजन		
• जिला	तहसील	नगर∕ग्राम	लगभग क्षेत्रफल (हेक्टेयर में)	के द्वारा प्राधिकृत अधिकारी	का वर्णन		
(1)	(2)	(3)357.3	% +jR + (4)¥	₆ 介。 (5)	بر (6) ن _{اب} ة		
बिलासपुर	कोटा	चपोरा	0.113 हे.	कार्यपालन अभियंता जल संसाधन संभाग, पेण्ड्रारोड.	पहुंच मार्ग हेतु		

भूमि का नक्शा (प्लान) अनुविभागीय अधिकारी (राजस्व), कोटा के कार्यालय में देखा जा सकता है.

विलासपुर, दिनांक 25 नवम्बर 2005

क्रमांक 2 अ-82/2005-2006. — चूंकि राज्य शासन को यह प्रतीत होता है कि इससे संलग्न अनुसूची के खाने (1) से (4) में वर्णित भूमि की अनुसूची के खाने (6) में उसके सामने दिये गये सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है, अथवा आवश्यकता पड़ने की संभावना है. अतः भू-अर्जन अधिनियम, 1894 (क्रमांक 1 सन् 1894) संशोधित भू-अर्जन अधिनियम, 1984 की धारा 4 की उपधारा (1) के उपबन्धों के अनुसार सभी संबंधित व्यक्तियों को इसके द्वारा इस आशय की सूचना दो जाती है कि राज्य शासन, इसके द्वारा, अनुसूची के खाने (5) में उल्लेखित अधिकारी को उक्त भूमि के संबंध में उक्त धारा 4 की उपधारा (2) द्वारा दी गई शक्तियों का प्रयोग करने के लिए प्राधिकृत करता है:—

अनुसूची

	- भृ	मि का वर्णन		धारा ४ को उपधारा (2)	सार्वजिन्क प्रयोजन
जिला	तहसील	नगर∕ग्राम	लगभग क्षेत्रफल (हेक्टेयर में)	के द्वारा प्राधिकृत अधिकारी	का वर्णन
(1)	(2)	(3)	. (4)	(5)	(6)
बिलासपुर	कोटा कोटा	र् तनपुर	3.049	कार्यपालन अभियंता जल संसाधन संभाग, पेण्ड्रारोड.	चांपी जलाशय मुख्य नहर हेतु.

भूमि का नक्शा (प्लान) अनुविभागीय अधिकारी (राजस्व), कोटा के कार्यालय में देखा जा सकता है.

बिलासपुर, दिनांक 29 नवम्बर 2005

क्रमांक 1 अ-82/2005-2006.—चूंकि राज्य शासन को यह प्रतीत होता है कि इससे संलग्न अनुसूची के खाने (1) से (4) में वर्णित भूमि की अनुसूची के खाने (6) में उसके सामने दिये गये सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है, अथवा आवश्यकता पड़ने की संभावना है. अतः भू-अर्जन अधिनियम, 1894 (क्रमांक 1 सन् 1894) संशोधित भू-अर्जन अधिनियम, 1984 की धारा 4 की उपधारा (1) के उपबन्धों के अनुसार सभी संबंधित व्यक्तियों को इसके द्वारा इस आशय की सूचना दी जाती है कि राज्य शासन, इसके द्वारा, अनुसूची के खाने (5) में उल्लेखित अधिकारी को उक्त भूमि के संबंध में उक्त धारा 4 की उपधारा (2) द्वारा दी गई शक्तियों का प्रयोग करने के लिए प्राधिकृत करता है :—

अनुसूची

•	9	्मि का वर्णन		धारा ४ की उपधारा (2)	सार्व्जनिक प्रयोजन	
जिला	तहसील	नगर/ग्राम	ं लगभग क्षेत्रफल (एकड़ में)	के द्वारा प्राधिकृत अधिकारी	का वर्णन	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	
बिलासपुर ्	बिल्हा,	पोंडी	8.78	कार्यपालन अभियंता, खारंगू जल संसाधन	बिलासपुर व्यपवर्तन् योजनाः नहर निर्माण हेतु.	

भूमि का नक्शा (प्लान) अ. वि. अ. (राजस्व), बिलासपुर के कार्यालय में देखा जा सकता है.

बिलासपुर, दिनांक 29 नवम्बर 2005

- क्रमांक 2 अ-82/2005-2006.—चूंकि राज्य शासन को द्वाह प्रतीत होता है कि इससे संलग्न अनुसूची के खाने (1) से (4) में वर्णित भूमि की अनुसूची के खाने (6) में उसके सामने दिये गये सार्वजनिक प्योजन के लिये आवश्यकता है, अथवा आवश्यकता पड़ने की संभावना है. अत: भू-अर्जन अधिनियम, 1894 (क्रमांक 1 सन् 1894) संशोधित भू-अर्जन अधिनियम, 1984 की धारा 4 की उपधारा (1) के उपबन्धों के अनुसार सभी संबंधित व्यक्तियों को इसके द्वारा इस आशय की सूचना दी जाती है कि राज्य शासन, इसके द्वारा, अनुसूची के खाने (5) में उल्लेखित अधिकारी को उक्त भूमि के संबंध में उक्त धारा 4 की उपधारा (2) द्वारा दी गई शक्तियों का प्रयोग करने के लिए प्राधिकृत करता है :—

. अनुसूर्च

		भूमि का वर्णन		धारा ४ की उपधारा (2)	सार्वजनिक प्रयोजन
जिला	तहसील	नगर/ग्राम	लगभग क्षेत्रफल -(एकड़ में)	्रे के द्वारा प्राधिकृत अधिकारी	का वर्णन
(1)	(2)	(3)	y (4)	(5)	(6)
विलासपुर	बिल्हा	बोड्सरा	+ 11.23	कार्यपालन अभियंता, खारंग जल संसाधन संभाग,	विलासपुर व्यपवर्तन योजना नहर निर्माण हेतु.
		-		बिलासपुर.	iez i ima eg.

भूमि का नक्शा (प्लान) अ. वि. अ. (राजस्व), बिलासपुर के कार्यालय में देखा जा सकता है.

बिलासपुर, दिनांक 1 दिसम्बर 2005

प्रकरण क्रमांक 3 अ-82/2005-2006.—चूंकि राज्य शासन को यह प्रतीत होता है कि इससे संलग्न अनुसूची के खाने (1) से (4) में वर्णित भूमि की अनुसूची के खाने (6) में उसके सामने दिये गये सार्वजिनक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है, अथवा आवश्यकता पड़ने की संभावना है. अतः भू-अर्जन अधिनियम, 1894 (क्रमांक 1 सन् 1894) संशोधित भू-अर्जन अधिनियम, 1984 की धारा 4 की उपधारा (1) के उपबन्धों के अनुसार सभी संबंधित व्यक्तियों को इसके द्वारा इस आशय की सूचना दी जाती है कि राज्य शासन, इसके द्वारा, अनुसूची के खाने (5) में उछेखित अधिकारी को उक्त भूमि के संबंध में उक्त धारा 4 की उपधारा (2) द्वारा दी गई शक्तियों का प्रयोग करने के लिए प्राधिकृत करता है:—

अनुसूची

	મૂ	मि का वर्णन		धारा ४ की उपधारा (2)	सार्वजनिक प्रयोजन	
- जिला	तहसील	नगर/ग्राम	लगभग क्षेत्रफल (हेक्टेयर में)	के द्वारा प्राधिकृत अधिकारी	ं का वर्णन	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	
बिलासपुर :	कोटा के कोटा व्यागनाम् कर	रतनपुर ^{;≈} ′ · ′	13.902 English (A)	कार्यपालन अभियंता, जल संसाधन संभाग, पेण्ड्रारोडः	माइनर नहर निर्माण हेतु ' (चांपी जलाशय)	

भूमि का नक्शा (प्लान) अनुविभागीय अधिकारी (राजस्व), कोटा के कार्यालय में देखा जा सकता है.

विलासपुर, दिनांक 3 दिसम्बर 2005

प्रकरण क्रमांक 11/ A 82/2003-04.—चूंकि राज्य शासन को यह प्रतीत होता है कि इससे संलग्न अनुसूची के खाने (1) से (4) में वर्णित भूमि की अनुसूची के खाने (6) में उसके सामने दिये गये सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है; अथवा आवश्यकता पड़ने की संभावना है. अत: भू-अर्जन अधिनियम, 1894 (क्रमांक 1 सन् 1894) संशोधित भू-अर्जन अधिनियम, 1984 की धारा 4 की उपधारा (1) के उपबन्धों के अनुसार सभी संबंधित व्यक्तियों को इसके द्वारा इस आशय की सूचना दी जाती है कि राज्य शासन, इसके द्वारा, अनुसूची के खाने (5) में उल्लेखित अधिकारी को उक्त भूमि के संबंध में उक्त धारा 4 की उपधारा (2) द्वारा दी गई शक्तियों का प्रयोग करने के लिए प्राधिकृत करता है:—

अनुसूची

	भूमि का वर्णन			धारा ४ की ्उपधारा (2)	सार्वजनिक प्रयोजन	
জিলা	तहसील	नगर/ग्राम	लगभग क्षेत्रफल (एकड् में)	के द्वारा . प्राधिकृत अधिकारी	का वर्णन	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	
बिलासपुर	तखतपुर -	मु रू	0.05	कार्यपालन अभियंता, लोक निर्माण विभाग, सेतु निर्माण संभाग, बिलासपुर.	सकरी भंवर विरकोनी मार्ग पर मनियारी नदी सेतु के पहुंच मार्ग हेतु.	

भूमि का नक्शा (प्लान) अनुविभागीय अधिकारी (राजस्व), कोटा के कार्यालय में देखा जा सकता है.

छत्तीसगढ़ के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार, विकासशील, कलेक्टर एवं पदेन उप-सचिव.

कार्यालय, कलेक्टर, जिला जांजगीर-चांपा, छत्तीसगढ़ एवं पदेन उप-सचिव, छत्तीसगढ़ शासन राजस्व विभाग

जांजगीर-चांपा, दिनांक 26 सितम्बर 2005

क्रमांक-क/भू-अर्जन/239.—चूंकि राज्य शासन को यह प्रतीत होता है कि इससे संलग्न अनुसूची के खाने (1) से (4) में वर्णित भूमि की अनुसूची के खाने (6) में उसके सामने दिये गये सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है, अथवा आवश्यकता पड़ने की संभावना है. अत: भू- अर्जन अधिनियम, 1894 (क्रमांक सन् 1894) संशोधित भू-अर्जन अधिनियम, 1984 की धारा 4 की उपधारा (1) के उपबन्धों के अनुसार सभी संबंधित व्यक्तियों को इसके द्वारा इस आशय की सूचना दी जाती है कि राज्य शासन, इसके द्वारा, अनुसूची के खाने (5) में उल्लेखित अधिकारी को उक्त भूमि के संबंध में उक्त धारा 4 की उपधारा (2) द्वारा दी गई शक्तियों का प्रयोग करने के लिए प्राधिकृत करता है. राज्य शासन यह भी निर्देश देता है कि उक्त अधिनियम की धारा 5 (3) के उपबंध, उक्त भूमि के संबंध में लागू नहीं होंगे, क्योंकि उसकी राय में उक्त अधिनियम की धारा 17 की उपधारा (1) के उपबंध उसके संबंध में लागू होते हैं :—

अनुसूची

		भूमि का वर्णन		धारा ४ की उपधारा (2)	सार्वजनिक प्रयोजन
जिला	. तहसील	नगर/ग्राम	लगभग क्षेत्रफल (हेक्टेयर में)	. के द्वारा प्राधिकृत अधिकारी	का वर्णन
(1)	(2)	(3)	(4)	. (5)	(6)
जांजगीर~चांपा	सकी	अमलडीहा प.ह.नं. 6	0.399	कार्यपालन यंत्री, नहर संभाग, खर्सिया.	मरकामगोढ़ी माइनर नहर निर्माण. (पूरक)

भूमि का नक्शा (प्लान) भू-अर्जन अधिकारी, हसदेव परियोजना, सक्ती के कार्यालय में देखा जा सकता है.

जांजगीर-चांपा, दिनांक 26 सितम्बर 2005

क्रमांक-क/भू-अर्जन/240.—चूंकि राज्य शासन को यह प्रतीत होता है कि इससे संलग्न अनुसूची के खाने (1) से (4) में वर्णित भूमि की अनुसूची के खाने (6) में उसके सामने दिये गये सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है, अथवा आवश्यकता पड़ने की संभावना है. अत: भू-अर्जन अधिनियम, 1894 (क्रमांक सन् 1894) संशोधित भू-अर्जन अधिनियम, 1984 की धारा 4 की उपधारा (1) के उपबन्धों के अनुसार सभी संबंधित व्यक्तियों को इसके द्वारा इस आशय की सूचना दी जाती है कि राज्य शासन, इसके द्वारा, अनुसूची के खाने (5) में उल्लेखित अधिकारों को उक्त भूमि के संबंध में उक्त धारा 4 की उपधारा (2) द्वारा दी गई शक्तियों का प्रयोग करने के लिए प्राधिकृत करता है. राज्य शासन यह भी निर्देश देता है कि उक्त अधिनियम को धारा 5 (अ) के उपबंध, उक्त भूमि के संबंध में लागू नहीं होंगे, क्योंकि उसकी राय में उक्त अधिनियम की धारा 17 की उपधारा (1) के उपबंध उसके संबंध में लागू होते हैं :—

अनुसूची

٠	·	*	भृमि का वर्णन	1 1	धारा ४ की उपधारा (2)	. · सा	र्वजनिक प्रयोजन
	जिला	तहसील	नगर/ग्राम	लगभग क्षेत्रफल	के द्वारा		का वर्णन
			* 3	- (हेक्टेयर में)	प्राधिकृत अधिकारी	• .	
۸- ن د	(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	. •	(6)
- ভাত	ागीर-चांपाः,	सकी	अरजुनी	0.109	कार्यपालन यंत्री, नहर संभाग,		ी सब माइनर नहर <i>ं</i>
•			प.ह.नं.10		खरिसया, जिला रायगढ़.	निर्पाण	।. (पूरक)

क्रमांक-क/भू-अर्जन/241.—चूंकि राज्य शासन को यह प्रतीत होता है कि इससे संलग्न अनुसूची के खाने (1) से (4) में वर्णित भूमि की अनुसूची के खाने (6) में उसके सामने दिये गये सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है, अथवा आवश्यकता पड़ने की संभावना है. अत: भू-अर्जन अधिनियम, 1894 (क्रमांक सन् 1894) संशोधित भू-अर्जन अधिनियम, 1984 की धारा 4 की उपधारा (1) के उपबन्धों के अनुसार सभी संबंधित व्यक्तियों को इसके द्वारा इस आशय की सूचना दी जाती है कि राज्य शासन, इसके द्वारा, अनुसूची के खाने (5) में उल्लेखित अधिकारी को उक्त भूमि के संबंध में उक्त धारा 4 की उपधारा (2) द्वारा दी गई शक्तियों का प्रयोग करने के लिए प्राधिकृत करता है. राज्य शासन यह भी निर्देश देता है कि उक्त अधिनियम की धारा 5 (अ) के उपबंध, उक्त भूमि के संबंध में लागू नहीं होंगे, क्योंकि उसकी राय में उक्त अधिनियम की धारा 17 की उपधारा (1) के उपबंध उसके संबंध में लागू होते हैं :—

अनुसूची

	भूमि का वर्णन			धारा ४ की उपधारा (2)	सार्वजनिक प्रयोजन
जिल <u>ा</u>	तहसील	नगर/ग्राम	लगभग क्षेत्रफल (हेक्टेयर में)	के द्वारा प्राधिकृत अधिकारी	का वर्णन
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)-
जांजगीर-चांपा	सकी .	मरकामगोढ़ी प.ह.नं _. 7	0.218	कार्यपालन यंत्री, नहर संभाग, खरसिया.	मरकामगोढी माइनर नहर निर्माण, (पूरक)

भूमि का नक्शा (प्लान) भू-अर्जन अधिकारी, हसदेव परियोजना, सक्ती/जांजगीर के कार्यालय में देखा जा सकता है.

जांजगीर-चांपा, दिनांक 26 सितम्बर 2005

क्रमांक-क/भू-अर्जन/242.—चूंकि राज्य शासन को यह प्रतीत होता है कि इससे संलग्न अनुसूची के खाने (1)-से (4) में वर्णित भूमि की अनुसूची के खाने (6) में उसके सामने दिये गये सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है, अथवा आवश्यकता पड़ने की संभावना है. अत: भू-अर्जन अधिनियम, 1894 (क्रमांक सन् 1894) संशोधित भू-अर्जन अधिनियम, 1984 की धारा 4 की उपधारा (1) के उपबन्धों के अनुसार सभी संबंधित व्यक्तियों को इसके द्वारा इस आशय की सूचना दी जाती है कि राज्य शासन, इसके द्वारा, अनुसूची के खाने (5) में उद्हेखित अधिकारी को उक्त भूमि के संबंध में उक्त धारा 4 की उपधारा (2) द्वारा दी गई शक्तियों का प्रयोग करने के लिए प्राधिकृत करता है. राज्य शासन यह भी निर्देश देता है कि उक्त अधिनियम की धारा 5 (अ) के उपबंध, उक्त भूमि के संबंध में लागू नहीं होंगे, क्योंकि उसकी राय में उक्त अधिनियम की धारा 17 की उपधारा (1) के उपबंध उसके संबंध में लागू होते हैं :—

अनुसूची

	3	भूमि का वर्णन		धारा ४ की उपधारा (2)	सार्वजनिक प्रयोजन	
जिला	तहसील	नगर∕ग्राम	लगभग क्षेत्रफल (हेक्टेयर में)	के द्वारा प्राधिकृत अधिकारी	का वर्णन	
(1)	(2)	(3')	.(4)	(5)	(6)	
जांजगीर-चांपा	जैजैपुर •	केकसभांठा प.ह.नं. 11	0.790	कार्यपालन यंत्री, बांगो नहर संभाग क्र. 3, सक्ती.	जाटा माइनर नहर निर्माण (पूरक)	

क्रमांक-क/भू-अर्जन/243.—चूंिक राज्य शासन को यह प्रतीत होता है कि इससे संलग्न अनुसूची के खाने (1) से (4) में वर्णित भूमि की अनुसूची के खाने (6) में उसके सामने दिये गये सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है, अथवा आवश्यकता पड़ने की संभावना है. अतः भू- अर्जन अधिनियम, 1894 (क्रमांक सन् 1894) संशोधित भू-अर्जन अधिनियम, 1984 की धारा 4 की उपधारा (1) के उपबन्धों के अनुसार सभी संबंधित व्यक्तियों को इसके द्वारा इस आशय की सूचना दी जाती है कि राज्य शासन, इसके द्वारा, अनुसूचों के उन्ते (5) में उल्लेखित अधिकारी को उक्त भूमि के संबंध में उक्त धारा 4 की उपधारा (2) द्वारा दी गई शक्तियों का प्रयोग करने के लिए प्राधिकृत करता है राज्य शासन यह भी निर्देश देता है कि उक्त अधिनियम की धारा 5 (अ) के उपबंध, उक्त भूमि के संबंध में लागू नहीं होंगे, क्योंकि उसकी गय में उक्त अधिनियम की धारा 17 की उपधारा (1) के उपबंध उसके संबंध में लागू होते हैं :—

अनुसूची

	भूमि का वर्णन			धारा ४ की उपधारा (2)	सार्वजनिक प्रयोजन	
. जिला	तहसील	नगर∕ग्राम .	लगभग क्षेत्रफल (हेक्टेयर में)	के द्वारा प्राधिकृत अधिकारी	्रका वर्णन	
· (i)	(2)	(3)	(4)	. (5)	(6)	
जांजगीर-चांपा	-जैजैपुर	केकराभांठा प.ह.नं. 5	: ₁₇ ·0.12,1	कार्यपालन यंत्री नहर _{ार स} ्र संभाग क्र.्3, सक्ती.	भोथीडीह माइनर नं. 2 नहर निर्माण. (पूरक)	

भूमि का नक्शा (प्लान) भू-अर्जन अधिकारी, हसदेव परियोजना, सक्ती के कार्यालय में देखा जा सकता है.

जांजगीर-चांपा, दिनांक 26 सितम्बर 2005

क्रमांक-क/भू-अर्जन/244. — चूंकि राज्य शासन को यह प्रतीत होता है कि इससे सलग्न अनुसूची के खान (1) से (4) में वर्णित भूमि की अनुसूची के खाने (6) में उसके सामने दिये गये सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है, अथवा आवश्यकता पड़ने की संभावना है. अतः भू- अर्जन अधिनियम, 1894 (क्रमांक सन् 1894) संशोधित भू-अर्जन अधिनियम, 1984 की धारा 4 की उपधारा (1) के उपबन्धों के अनुसार सभी संबंधित व्यक्तियों को इसके द्वारा इस आशय की सूचना दी जाती है कि राज्य शासन, इसके द्वारा, अनुसूची के खाने (5) में उल्लेखित अधिकारी को उक्त भूमि के संबंध में उक्त धारा 4 की उपधारा (2) द्वारा दी गई शक्तियों का प्रयोग करने के लिए प्राधिकृत करता है. राज्य शासन यह भी निर्देश देता है कि उक्त अधिनियम की धारा 5 (अ) के उपबंध, उक्त भूमि के संबंध में लागू नहीं होंगे, क्योंकि उसकी राय में उक्त अधिनियम की धारा 17 की उपधारा (1) के उपबंध उसके संबंध में लागू होते हैं:—

अनुसूची

•	•	भूमि का वर्णन		धारा ४ की उपधारा (2)	सार्वजनिक प्रयोजन
जिला	तहसील	नग्र√ग्राम	.लगभग क्षेत्रफल (हेक्टेयर में)	़के द्वारा प्राधिकृत अधिकारी	ं का वर्णन
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
जांजगीर-चांपा	जैजैपुर	केकराभांठा प.इ.नं. 8	0.088	कार्यपालन यंत्री नहर संभाग क्र. 3, सक्ती.	मुरलोडीह डिस्ट्री. नहर निर्माण (पूरक)

क्रमांक-क/भू-अर्जन/245.—चूंकि राज्य शासन को यह प्रतीत होता है कि इससे संलग्न अनुसूची के खाने (1) से (4) में वर्णित भूमि की अनुसूची के खाने (6) में उसके सामने दिये गये सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है, अथवा आवश्यकता एड़ने की संभावना है. अत: भू- अर्जन अधिनियम, 1894 (क्रमांक सन् 1894) संशोधित भू-अर्जन अधिनियम, 1984 की धारा 4 की उपधारा (1) के उपबन्धों के अनुसार सभी संबंधित व्यक्तियों को इसके द्वारा इस आशय की सूचना दो जाती है कि राज्य शासन, इसके द्वारा, अनुसूची के खाने (5) में उल्लेखित अधिकारी को उक्त भूमि के संबंध में उक्त धारा 4 की उपधारा (2) द्वारा दी गई शक्तियों का प्रयोग करने के लिए प्राधिकृत करता है. राज्य शासन यह भी निर्देश देता है कि उक्त अधिनियम की धारा 5 (अ) के उपबंध, उक्त भूमि के संबंध में लागू नहीं होंगे, क्योंकि उसकी राय में उक्त अधिनियम की धारा 17 की उपधारा (1) के उपबंध उसके संबंध में लागू होते हैं:—

अंनुसूची

	•	भूमि का वर्णन		धारा ४ की उपधारा (2)	सार्वजनिक प्रयोजन
ज़िला	तहसील	नगर∕ग्राम	लगभग क्षेत्रफल . (हेक्टेयर में)	के द्वारा प्राधिकृतं अधिकारी	का वर्णन ,
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	. (6)
जांजगीर-चांपा *- *:	सकी ''':	खम्हरिया प.ह.नं. 6	0.118	कार्यपालन यंत्री, नहर संभाग क्र. 3, सक्ती.	खम्हरिया माइII नहर निर्माण हेतु.

भूमि का नक्शा (प्लान) भू-अर्जन अधिकारी, हसदेव परियोजना, सक्ती/जांजगीर के कार्यालय में देखा जा सकता है.

जांजगीर-चांपा, दिनांक 26 सितम्बर 2005

क्रमांक-क/भू-अर्जन/246.— चूँिक राज्य शासन को यह प्रतीत होता है कि इससे संलग्न अनुसूची के खाने (1) से (4) में वर्णित भूमि की अनुसूची के खाने (6) में उसके सामने दिये गये सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है, अथवा आवश्यकता एड़ने की संभावना है. अत: भू-अर्जन अधिनियम, 1894 (क्रमांक सन् 1894) संशोधित भू-अर्जन अधिनियम, 1984 की धारा 4 की उपधारा (1) के उपबन्धों के अनुसार सभी संबंधित व्यक्तियों को इसके द्वारा इस आशय की सूचना दी जाती है कि राज्य शासन, इसके द्वारा, अनुसूची के खाने (5) में उल्लेखित अधिकारी को उक्त भूमि के संबंध में उक्त धारा 4 की उपधारा (2) द्वारा दी गई शक्तियों का प्रयोग करने के लिए प्राधिकृत करता है. राज्य शासन यह भी निर्देश देता है कि उक्त अधिनियम की धारा 5 (अ) के उपबंध, उक्त भूमि के संबंध में लागू नहीं होंगे, क्योंकि उसकी राय में उक्त अधिनियम की धारा 17 की उपधारा (1) के उपबंध उसके संबंध में लागू होते हैं :—

अनुसूची

	. 9	र्मि का वर्णन		धारा 4 की उपधारा (2)	सार्वजनिक प्रयोजन	
जिला	तहसील	नगर∕ग्राम	लगभग क्षेत्रफल (हेक्टेयर में)	के द्वारा प्राधिकृत अधिकारी ╭	का वर्णन	
(1)	(2)	(3)	(4)	. (5)	. (6)	
जांजगीर-चांपा	जैजैपुर	खजुरानी प.ह.नं. 11	0.230	कार्यपालन यंत्री, नहर संभाग क्र. 3, सक्ती.	खजुरानी माइनर नहर.	

क्रमांक-क/भू-अर्जन/247.—चूंकि राज्य शासन को यह प्रतीत होता है कि इससे संलग्न अनुसूची के खाने (1) से (4) में वर्णित भूमि की अनुसूची के खाने (6) में उसके सामने दिये गये सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है, अथवा आवश्यकता पड़ने की संभावना है. अत: भू-अर्जन अधिनियम, 1894 (क्रमांक सन् 1894) संशोधित भू-अर्जन अधिनियम, 1984 की धारा 4 की उपधारा (1) के उपबन्धों के अनुसार सभी संबंधित व्यक्तियों को इसके द्वारा इस आशय की सूचना दी जाती है कि राज्य शासन, इसके द्वारा, अनुसूची के खाने (5) में उल्लेखित अधिकारी का उक्त भूमि के संबंध में उक्त धारा 4 की उपधारा (2) द्वारा दी गई शक्तियों का प्रयोग करने के लिए प्राधिकृत करता है. राज्य शासन यह भी निर्देश देता है कि उक्त अधिनियम की धारा 5 (अ) के उपबंध, उक्त भूमि के संबंध में लागू नहीं होंगे, क्योंकि उसकी राय में उक्त अधिनियम की धारा 17 की उपधारा (1) के उपबंध उसके संबंध में लागू होते हैं :—

अनुसूची:

	भू	मि का वर्णन		धारा 4 की ं उपधारा (2)	सार्वजनिक प्रयोजन	
जिला	तहसील	नगर/ग्राम्	लगभग क्षेत्रफल (हेक्टेयर में)	के द्वारा . प्राधिकृत अधिकारी	का वर्णन	•
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	
जांजगीर-चांपा -	- इ जैजैंपु ऱ्न	भोथीडीह प.ह.नं. 5	0.730	कार्यपालनः यत्रीं, नहर संभागः — : क्र. 3, सक्ती.	भोथीडीह-माइनर नं: 2 नहर निर्माण. (पूरक)	

भूमि का नक्शा (प्लान) भू-अर्जन अधिकारी, हसदेव परियोजना, सक्ती/जांजगीर के कार्यालय में देखा जा सकता है.

जांजगीर-चांपा, दिनांक 26 सितम्बर 2005

क्रमांक-क/भू-अर्जन/248.—चूंकि राज्य शासन को यह प्रतीत होता है कि इससे संलग्न अनुसूची के खाने (1) से (4) में वर्णित भूमिं की अनुसूची के खाने (6) में उसके सामने दिये गये सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है, अथवा आवश्यकता पड़ने की संभावना है. अत: भू- अर्जन अधिनियम, 1894 (क्रमांक सन् 1894) संशोधित भू-अर्जन अधिनियम, 1984 की धारा 4 की उपधारा (1) के उपबन्धों के अनुसार सभी संबंधित व्यक्तियों को इसके द्वारा इस आशय की सूचना दी जाती है कि राज्य शासन, इसके द्वारा, अनुसूची के खाने (5) में उल्लेखित अधिकारी को उक्त भूमि के संबंध में उक्त धारा 4 की उपधारा (2) द्वारा दी गई शक्तियों का प्रयोग करने के लिए प्राधिकृत करता है. राज्य शासन यह भी निर्देश देता है कि उक्त अधिनियम की धारा 5 (अ) के उपबंध, उक्त भूमि के संबंध में लागू नहीं होंगे, क्योंकि उसकी राय में उक्त अधिनियम की धारा 17 की उपधारा (1) के उपबंध उसके संबंध में लागू होते हैं :—

अनुसूची

भूमि का वर्णन	धारा 4 की उपधारा (2) सार्वजनिक प्रयोजन
	सेत्रफल के द्वारा का वर्णन यर में) प्राधिकृत अधिकारी
(1) (2) (3)	1) (5) (6)
जाजगीर-चांपा ै जैजैपुर कोटेतरा 0.0	61 कार्यपालन यंत्री, नहर संभाग मुरलीडीह माइनर नहर क्र. 3, सक्ती. निर्माण हेतु.

क्रमांक-क/भू-अर्जन/249. — चूंकि राज्य शासन को यह प्रतीत होता है कि इससे संलग्न अनुसूची के खाने (1) से (4) में वर्णित भूमि की अनुसूची के खाने (6) में उसके सामने दिये गये सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता हैं, अथवा आवश्यकता पड़ने की संभावना हैं. अत: भू- अर्जन अधिनियम, 1894 (क्रमांक सन् 1894) संशोधित भू-अर्जन अधिनियम, 1984 की धारा 4 की उपधारा (1) के उपबन्धों के अनुसार सभी संबंधित व्यक्तियों को इसके द्वारा इस आशय की सूचना दी जाती है कि राज्य शासन, इसके द्वारा, अनुसूची के खाने (5) में उल्लेखित अधिकारी का उक्त भूमि के संबंध में उक्त धारा 4 की उपधारा (2) द्वारा दी गई शक्तियों का प्रयोग करने के लिए प्राधिकृत करता है. राज्य शासन यह भी निर्देश देता है कि उक्त अधिनियम की धारा 5 (अ) के उपबंध, उक्त भूमि के संबंध में लागू नहीं होंगे, क्योंकि उसकी राय में उक्त अधिनियम की धारा 17 की उपधारा (1) के उपबंध उसके संबंध में लागू होते हैं:—

अनुसूची

•		મૃ	मि का वर्णन		धारा ४ की उपधारा (2)	सार्वजनिक प्रयोजन
· **	जिला	तहसील	नगर⁄ग्रामं '	् लगभग क्षेत्रफल (हेक्टेयर में)	के द्वारा प्राधिकृत अधिकारी	क्यु वर्णन
	(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
ত	ांजगीर-चांपा	[ा] जैजैपुर	जैजैपुर	0.060	कौर्यपालन यंत्री, बांगो नहर ः संभाग क्र. 3, सक्ती.	भाठापारा माइनर-वहर ^{६ ।}

भूमि का नक्शा (प्लान) भू-अर्जन अधिकारी, हसदेव परियोजना, सक्ती/जांजगीर के कार्यालय में देखा जा सकता है.

जांजगीर-चांपा, दिनांक 26 सितम्बर 2005

क्रमांक-क/भू-अर्जन/250.—चूंकि राज्य शासन को यह प्रतीत होता है कि इससे संलग्न अनुसूची के खाने (1) से (4) में वर्णित भूमि की अनुसूची के खाने (6) में उसके सामने दिये गये सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है, अथवा आवश्यकता पड़ने को संभावना है. अत: भू- अर्जन अधिनियम, 1894 (क्रमांक सन् 1894) संशोधित भू-अर्जन अधिनियम, 1984 की धारा 4 की उपधारा (1) के उपबन्धों के अनुसार सभी संबंधित व्यक्तियों को इसके द्वारा इस आशय की सूचना दी जाती है कि राज्य शासन, इसके द्वारा, अनुसूची के खाने (5) में उल्लेखित अधिकारी को उक्त भूमि के संबंध में उक्त धारा 4 की उपधारा (2) द्वारा दी गई शक्तियों का प्रयोग करने के लिए प्राधिकृत करता है. राज्य शासन यह भी निर्देश देता है कि उक्त अधिनियम की धारा 5 (अ) के उपबंध, उक्त भूमि के संबंध में लागू नहीं होंगे, क्योंकि उसकी राय में उक्त अधिनियम की धारा 17 की उपधारा (1) के उपबंध उसके संबंध में लागू होते हैं :—

अनुसूची

भूमि का वर्णन				धारा ४ की उपधारा (2)	सार्वजनिक प्रयोजन
जिला	तहसील	नगर∕ग्राम	लगभग क्षेत्रफल (हेक्टेयर में)	के द्वारा प्राधिकृत अधिकारी	का वर्णन
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
जांजगीर-चांपा	जैजैपुर	भोथीडीह प.ह.नं. 5	0.093	कार्यपालन यंत्री, नहर संभाग क्र. 3, सक्ती.	भोथीडीह माइनर नं. 3, नहर निर्माण. (पूरक)

क्रमांक-क/भू-अर्जन/251. — चूंकि राज्य शासन को यह प्रतीत होता है कि इससे संलग्न अनुसूची के खाने (1) से (4) में वर्णित भूमि की अनुसूची के खाने (6) में उसके सामने दिये गये सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है, अथवा आवश्यकता पड़ने की संभावना है. अतः भू- अर्जन अधिनियम, 1894 (क्रमांक सन् 1894) संशोधित भू-अर्जन अधिनियम, 1984 की धारा 4 की उपधारा (1) के उपबन्धों के अनुसार सभी संबंधित व्यक्तियों को इसके द्वारा इस आशय की सूचना दी जाती है कि राज्य शासन, इसके द्वारा, अनुसूची के खाने (5) में उल्लेखित अधिकारी को उक्त भूमि के संबंध में उक्त धारा 4 की उपधारा (2) द्वारा दी गई शक्तियों का प्रयोग करने के लिए प्राधिकृत करता है. राज्य शासन यह भी निर्देश देता है कि उक्त अधिनियम की धारा 5 (अ) के उपबंध, उक्त भूमि के संबंध में लागू नहीं होंगे, क्योंकि उसकी राय में उक्त अधिनियम की धारा 17 की उपधारा (1) के उपबंध उसके संबंध में लागू होते हैं:—

अनुसूची

	પ ્ર	मि का वर्णन		धारा ४ की उपधारा (2)	सार्वजनिक प्रयोजन्
जिला	तहसील ≁	नगर/ग्राम	लगभग क्षेत्रफल (हेक्टेयर में)	के द्वारा प्राधिकृत अधिकारी	का वर्णन
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
जांजगीर-चांपा	मालखरौंदा	सपिया	1.594	कार्यपालन यंत्री, मिनीमाता बांगो नहर संभाग क्र. 4, डभरा.	कुरदा वितरक नहर निर्माण

भूमि का नक्शा (प्लान) भू-अर्जन अधिकारी, हसदेव परियोजना, सक्ती के कार्यालय में देखा जा सकता है.

जांजगीर-चांपा, दिनांक 26 सितम्बर 2005

क्रमांक-क/भू-अर्जन/252.— चूंकि राज्य शासन को यह प्रतीत होता है कि इससे संलग्न अनुसूची के खाने (1) से (4) में वर्णित भूमि की अनुसूची के खाने (6) में उसके सामने दिये गये सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है, अथवा आवश्यकता पड़ने की संभावना है. अतः भू- अर्जन अधिनियम, 1894 (क्रमांक सन् 1894) संशोधित भू-अर्जन अधिनियम, 1984 की धारा 4 की उपधारा (1) के उपबन्धों के अनुसार सभी संबंधित व्यक्तियों को इसके द्वारा इस आशय की सूचना दी जाती है कि राज्य शासन, इसके द्वारा, अनुसूची के खाने (5) में उल्लेखित अधिकारी को उक्त भूमि के संबंध में उक्त धारा 4 की उपधारा (2) द्वारा दी गई शक्तियों का प्रयोग करने के लिए प्राधिकृत करता है. राज्य शासन यह भी निर्देश देता है कि उक्त अधिनियम की धारा 5 (अ) के उपबंध, उक्त भूमि के संबंध में लागू नहीं होंगे, क्योंकि उसकी राय में उक्त अधिनियम की धारा 17 की उपधारा (1) के उपबंध उसके संबंध में लागू होते हैं :—

अनुसूची

		a.	मि का वर्णन		धारा ४ की उपधारा (2)	सार्वजनिक प्रयोजन	
	जिला	तहसील	नगर/ग्राम	लगभग क्षेत्रफल (हेक्टेयर में)	के द्वारा प्राधिकृत अधिकारी	का वर्णन	
	(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	
•	जांजगीर -चां पा	मालखरौदा	परसा प.ह.नं. 10	0.060	कार्यपालन यंत्री, नहर संभाग क्र. 4, डभरा.	टेलमाइनर/ परसा माइनर नहर निर्माण.	

क्रमांक-क/भू-अर्जन/316.—चूंिक राज्य शासन को यह प्रतीत होता है कि इससे संलग्न अनुसूची के खाने (1) सं (4) में वर्णित भूमि की अनुसूची के खाने (5) में उसके सामने दिये गये सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है, अथवा आवश्यकता पड़ने की संभावना है. अत: भू- अर्जन अधिनियम, 394 (क्रमांक सन् 1894) संशोधित भू-अर्जन अधिनियम, 1984 की धारा 4 की उपधारा (1) के उपवन्धों के अनुसार मभी संविधत व्यक्तियों को इसके द्वारा इस आशय की सूचना दी जाती है कि राज्य शासन, इसके द्वारा, अनुसूची के खाने (5) में उल्लेखित अधिकारी को उक्त भूमि के संबंध में उक्त धारा 4 की उपधारा (2) द्वारा दी गई शक्तियों का प्रयोग करने के लिए प्राधिकृत करता है. राज्य शासन यह भी निर्देश देता है कि उक्त अधिनियम को भार 15 (अ) के उपबंध, उक्त भूमि के संबंध में लागू नहीं होंगे, क्योंकि उसकी राय में उक्त अधिनियम की धारा 17 की उपधारा (1) के उपवंध उसके संबंध में लागू होते हैं:—

अनुसूची

	•	भूमि का वर्णन		धारा ४ की उपधारा (2)	सार्वजनिक प्रयोजन
जिला	तहसील	नगर/ग्राम	लगभग क्षेत्रफल (हेक्टेयर में)	के द्वारा प्राधिकृत अधिकारी [.]	का वर्णन
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
जांजगीर-चांपा · ·	सकेंी	अंजोरीपाली	0.032	कार्यपालन यंत्री, मिनीमाता बांगो नहर संभाग क्र. 5, खरसिया.	' अंजोरीपार्ली माइनर

भूमि का नक्शा (प्लान) भू-अर्जन अधिकारी, हसदेव परियोजना, सक्ती के कार्यालय में देखा जा सकता है.

जांजगीर-चांपा, दिनांक 19 अक्टूबर 2005

क्रमांक-क/भू-अर्जन/317.— चूंकि राज्य शासन को यह प्रतीत होता है कि इससे संलग्न अनुसूची के खाने (1) से (4) में वर्णित भूमि को अनुसूची के खाने (6) में उसके सामने दिये गये सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है, अथवा आवश्यकता पड़ने की संभावना है. अत: भू- अर्जन अधिनियम, 1894 (क्रमांक सन् 1894) संशोधित भू-अर्जन अधिनियम, 1984 की धारा 4 की उपधारा (1) के उपयन्धों के अनुसार सभी संयंधित व्यक्तियों को इसके द्वारा इस आशय की सूचना दी जाती है कि राज्य शासन, इसके द्वारा, अनुसूची के खाने (5) में उल्लेखित अधिकारी को उक्त भूमि के संबंध में उक्त धारा 4 की उपधारा (2) द्वारा दी गई राज्यि का प्रयोग करने के लिए प्राधिकृत करता है. राज्य शासन यह भी निर्देश देता है कि उक्त अधिनियम की धारा 5 (अ) के उपवंध, उक्त भूमि के संबंध में लागू नहीं होंगे, क्योंकि उसकी राय में उक्त अधिनियम को धारा 17 की उपधारा (1) के उपबंध उसके संबंध में लागू होते हैं :—

अनुसूची

भूमि का वर्णन				. धारा ४ की उपधारा (2)	सार्वजनिक प्रयोजन
जिला	तहसील	नगर/ग्राम	लगभग क्षेत्रफल (हेक्टेयर में)	के द्वारा प्राधिकृत अधिकारी	्का वर्णन
(1)	(2)	(3)	(4) '	(5)	(6)
जांजगीर-चांपा	सक्ती	घोघस	0.284	कार्यपालन यंत्री, मिनीमाता बांगो नहर संभाग क्र. 5, खरसिया.	घोघरा माइनर

क्रमांक-क/भू-अर्जन/318.—चूंकि राज्य शासन को यह प्रतीत होता है कि इससे संलग्न अनुसूची के खाने (1) से (4) में विर्णत भूमि की अनुसूची के खाने (6) में उसके सामने दिये गये सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है, अथवा आवश्यकता गड़ने की संभावना है, अत: भू अर्जन अधिनियम, 1894 (क्रमांक सन् 1894) संशोधित भू-अर्जन अधिनियम, 1984 की धारा 4 की उपधारा (1) के उपवन्धों के अनुसार सभी संबंधित व्यक्तियों को इसके द्वारा इस आशय की सूचना दी जातो है कि राज्य शासन, इसके द्वारा, अनुसूची के खाने (5) में उल्लेखित अधिकारों को उक्त भूमि के संबंध में उक्त धारा 4 की उपधारा (2) द्वारा दी गई शक्तियों का प्रयोग करने के लिए प्राधिकृत करता है, राज्य शासन यह भी निर्देश देता है कि उक्त अधिनियम की धारा 5 (अ) के उपबंध, उक्त भूमि के संबंध में लागू नहीं होंगे, क्योंकि उसकी राय में उक्त अधिनियम की धारा 17 की उपधारा (1) के उपवंध उसके संबंध में लागू होते हैं :—

अनुसूची

	9	भूमि का वर्णन		धारा ४ की उपधारा (2)	ं सार्वजनिक प्रयोजन
जिला	तहसील	नगर/ग्राम	लगभग क्षेत्रफल (हेक्टेयर में)	के द्वारा प्राधिकृत अधिकारी	का वर्णन
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	. (6)
जांजगीर-चांपा	सक्ती	जुङ्गा	3.119	कार्यपालन यंत्री, मिनीमाता वांगो नहर संभाग क्र. 5, खरसिया.	नवागांव माइनर

भूमि का नक्शा (प्लान) भू-अर्जन अधिकारी, हसदेव परियोजना, सक्ती के कार्यालय में देखा जा सकता है.

जांजगीर-चांपा, दिनांक 19 अक्टूबर 2005

क्रमांक-क/भू-अर्जन/319.—चूंकि राज्य शासन को यह प्रतीत होता है कि इससे संलग्न अनुसूर्ची के खाने (1) से (4) में वर्णित भूमि की अनुसूर्ची के खाने (6) में उसके सामने दिये गये सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है, अथवा आवश्यकता पड़ने की संभावना है. अत: भू-अर्जन अधिनियम, 1894 (क्रमांक सन् 1894) संशोधित भू-अर्जन अधिनियम, 1984 की धारा 4 की उपधारा (1) के उपबन्धों के अनुसार सभी संबंधित व्यक्तियों को इसके द्वारा इस आशय की सूचना दी जाती है कि राज्य शासन, इसके द्वारा, अनुसूची के खाने (5) में उल्लेखित अधिकारी को उक्त भूमि के संबंध में उक्त धारा 4 की उपधारा (2) द्वारा दी गई शक्तियों का प्रयोग करने के लिए प्राधिकृत करता है. राज्य शासन यह भी निर्देश दंता है कि उक्त अधिनियम की धारा 5 (अ) के उपबंध, उक्त भूमि के संबंध में लागू नहीं होंगे, क्योंकि उसकी राय में उक्त अधिनियम की धारा 17 की उपधारा (1) के उपबंध उसके संबंध में लागू होते हैं :—

अंनुसूची

	9	ा्मि का वर्णन [े]		धारा ४ की उपधारा (2)	सार्वजनिक प्रयोजन
- जिला	तहसील	नगर/ग्राम	लगभग क्षेत्रफल	के द्वारा	का वर्णन
		• ′ .	(हेक्टेयर में)	प्राधिकृत अधिकारी	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
जांजगीर-चांपा	्रस्की	सेंदरी	0.053	कार्यपालन यंत्री, मिनीमाता बांगो	पुटेकेला उप वितरक
		gartin 🙀 🕍	and the second of the second	नहर सुभाग् क्र. ड. खरसिया.	•

क्रमांक-क/भू-अर्जन/320.—चूंकि राज्य शासन को यह प्रतीत होता है कि इससे संलग्न अनुसूची के खाने (1) से (4) में वर्णित भृमि की अनुसूची के खाने (6) में उसके सामने दिये गये सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है, अथवा आवश्यकता पड़ने की संभावना है. अत: भृ-अर्जन अधिनियम, 1894 (क्रमांक सन् 1894) संशोधित भू-अर्जन अधिनियम, 1984 की धारा 4 की उपधारा (1) के उपबन्धों के अनुसार सभी संबंधित व्यक्तियों को इसके द्वारा इस आशय की सूचना दी जाती है कि राज्य शासन, इसके द्वारा, अनुसूची के खाने (5) में उल्लेखित अधिकारी को उक्त भूमि के संबंध में उक्त धारा 4 की उपधारा (2) द्वारा दी गई शक्तियों का प्रयोग करने के लिए प्राधिकृत करता है. राज्य शासन यह भी निर्देण देता है कि उक्त अधिनियम की धारा 5 (अ) के उपबंध, उक्त भूमि के संबंध में लागू नहीं होंगे, क्योंकि उसकी राय में उक्त अधिनियम की धारा 17 की उपधारा (1) के उपबंध उसके संबंध में लागू होते हैं :—

अनुसूची

		भूमि का वर्णन 🕝		धारा ४ की उपधारा (2)	सार्वजनिक प्रयोजन	
जिला	तहसील	नगर/ग्राम	लगभग क्षेत्रफल (हेक्टेयर में)	 के द्वारा प्राधिकृत अधिकारी 	कावर्णन	
. (1)	(2).	(3)	(4)	(5)	(6)	
्जांजग़ीर-त्वांपा	_{निस्} जैजैपुर	-जैज <u>ेपुर</u>	- 0.509	कार्यपालन यंत्री, नहर संभाग ऋ 3, सक्ती	ं*ं जिजेपुर मीड़नर नं. 2 नहर ् निर्माण.	

भूमि का नक्शा (प्लान) भू-अर्जन अधिकारी, हसदेव परियोजना, सक्ती के कार्यालय में देखा जा सकता है.

जांजगीर-चांपा, दिनांक 19 अक्टूबर 2005

क्रमांक-क/भू-अर्जन/321.—चूंकि राज्य शासन को यह प्रतीत होता है कि इससे संलग्न अनुसूची के खाने (1) सं (4) में वार्णत भूमि की अनुसूची के खाने (6) में उसके सामने दिये गये सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है, अथवा आवश्यकता पड़ने की संभावना है, अत: भ् अर्जन अधिनियम, 1894 (क्रमांक सन् 1894) संशोधित भू-कर्न अधिनियम, 1984 की धारा 4 की उपधारा (1) के उपवन्धों के अनुसार सभी संयंधित व्यक्तियों को इसके द्वारा इस आशय की सूचना दी जाती है कि राज्य शासन, इसके द्वारा, अनुसूची के खाने (5) में उल्लेखित अधिकारी को उक्त भूमि के संबंध में उक्त धारा 4 की उपधारा (2) द्वारा दी गई शक्तियों का प्रयोग करने के लिए प्राधिकृत करता है. राज्य शासन यह भी निर्देश देता है कि उक्त अधिनियम की धारा 5 (अ) के उपबंध, उक्त भूमि के संबंध में लागू नहीं होंगे, क्योंकि उसकी राय में उक्त अधिनियम की धारा 17 की उपधारा (1) के उपबंध उसके संबंध में लागू होते हैं :—

अनुसूची

		भूमि का वर्णन		धारा ४ की उपधारा (2)	सार्वजनिक प्रयोजन
जिला	तहसील	नगर/ग्राम	लगभग क्षेत्रफल (हेक्टेयर में)	कं द्वारा प्राधिकृत अधिकारी	का वर्णन
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
जांजगीर-चांपा	जैजैपुर [ं]	जैजेंपुर	0.228	कार्यपालन यंत्री, नहर संभाग क्र. 3, सक्ती.	. परसाडोह वितरक नहर निर्माण.

क्रमांक-क/भू-अर्जन/322.—चूंिक राज्य शासन को यह प्रतीत होता है कि इससे संलग्न अनुसूची के खाने (1) से (4) में वर्णित भूमि की अनुसूची के खाने (6) में उसके सामने दिये गये सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है, अथवा आवश्यकता पड़ने की संभावना है. अत: भू-अर्जन अधिनियम, 1894 (क्रमांक सन् 1894) संशोधित भू-अर्जन अधिनियम, 1984 की धारा 4 की उपधारा (1) के उपबन्धों के अनुसार सभी संविधित व्यक्तियों को इसके द्वारा इस आशय की सूचना दी जाती है कि राज्य शासन, इसके द्वारा, अनुसूची के खाने (5) में उल्लेखित अधिकारी को उक्त भूमि के संबंध में उक्त धारा 4 की, उपधारा (2) द्वारा दो गई शक्तियों का प्रयोग करने के लिए प्राधिकृत करता है, राज्य शासन यह भी निर्देण देता है कि उक्त अधिनियम की धारा 5 (अ) के उपबंध, उक्त भूमि के संबंध में लागू नहीं होंगे, क्योंकि उसकी राय में उक्त अधिनियम की धारा 17 की उपधारा (1) के उपबंध उसके संबंध में लागू होते हैं :—

अनुसूची

		भूमि का व़र्णन	धारा ४ की उपधारा (2)	. सार्वजनिक प्रयोजन	
-जिला	तहसील	नगर/ग्राम	लगभग क्षेत्रफल (हेक्टेयर भें)	के द्वारा प्राधिकृत अधिकारी	का वर्णन
(+)	.(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
जांजगीर-चांपा	डभरा	कुसमूल 🗥	0.255	कार्यपालन यंत्री; मिनीमाती बीगीं नहर संभाग क्र. 4, डभरा:	सिंधरा वितरकः

भूमि का नक्शा (प्लान) भू-अर्जन अधिकारी, हसदेव परियोजना, सक्ती के कार्यालय में देखा जा सकता है.

जांजगीर-चांपा, दिनांक 19 अक्टूबर 2005

क्रमांक-क/भू-अर्जन/323.—चूंकि राज्य शासन को यह प्रतीत होता है कि इससे संलग्न अनुसूची के खाने (1) से (4) में वर्णित भूमि की अनुसूची के खाने (6) में उसके सामने दिये गये सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है, अथवा आवश्यकता एड़ने की संभावना है. अतः भू-अर्जन अधिनियम, 1894 (क्रमांक सन् 1894) संशोधित भू-अर्जन अधिनियम, 1984 की धारा 4 की उपधारा (1) के उपबन्धों के अनुसार सभी संबंधित व्यक्तियों को इसके द्वारा इस आशय की सूचना दी जाती है कि राज्य शासन, इसके द्वारा, अनुसूची के खाने (5) में उल्लेखित अधिकारी का उक्त भूमि के संबंध में उक्त धारा 4 की उपधारा (2) द्वारा दी गई शक्तियों का प्रयोग करने के लिए प्राधिकृत करता है. राज्य शासन यह भी निर्देश देता है कि उक्त अधिनियम की धारा 5 (अ) के उपबंध, उक्त भूमि के संबंध में लागू नहीं होंगे, क्योंकि उसकी राय में उक्त अधिनियम की धारा 17 को उपधारा (1) के उपबंध उसके संबंध में लागू होते हैं :—

अनुसूची

		मि का वर्णन		धारा ४ की उपधारा (2)	सार्वजनिक प्रयोजन	
जिला	तहसील	नगर∕ग्राम	लगभग क्षेत्रफल (हेक्टेयर में)	के द्वारा प्राधिकृत अधिकारी	का वर्णन	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	
जांजगीर-चांपा	मालखरौदा	कुलवा	0.221	कार्यपालन यंत्री, मिनीमाता बांगो नहर संभाग क्र. 4, डभरा.	कुधरी सब डीवाय	

क्रमांक-क/भू-अर्जन/324.—चूंकि राज्य शासन को यह प्रतीत होता है कि इससे संलग्न अनुसूची के खाने (1) से (4) में वर्णित भूमि को अनुसूची के खाने (6) में उसके सामने दिये गये सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है, अथवा आवश्यकता पड़ने की संभावना है, अत: भु-अर्जन अधिनियम, 1894 (क्रमांक सन् 1894) संशोधित भू-अर्जन अधिनियम, 1984 की धारा 4 की उपधारा (1) के उपवन्धों के अनुसार सभी मंबिधत व्यक्तियों को इसके द्वारा इस आशय की सूचना दी जाती है कि राज्य शासन, इसके द्वारा, अनुसूची के खाने (5) में उल्लेखित अधिकारी का उक्त भूमि के संबंध में उक्त धारा 4 की उपधारा (2) द्वारा दी गई शक्तियों का प्रयोग करने के लिए प्राधिकृत करता है. राज्य शासन यह भी निर्देश देता है कि उक्त अधिनियम की धारा 5 (अ) के उपबंध, उक्त भूमि के संबंध में लागू नहीं होंगे, क्योंकि उसकी राय में उक्त अधिनियम की धारा 17 की उपधारा (1) के उपबंध उसके संबंध में लागू होते हैं :—

अनुसूची

भूमि का वर्णन				धारा ४ की उपधारा (2)	सार्वजनिक प्रयोजन
जिला .	तहसील	नगर/ग्राम	लगभग क्षेत्रफल (हेक्टेयर में)	के द्वारा प्राधिकृत अधिकारी	का वर्णन
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	. (6)
जांजगीर-चांपा	मालखरौदा	बोडासागर	0.516	कार्यपालन यंत्री, मिनीमाता ग्रांगो	बोड़ासागर माइनर
المؤتاق	1 1	प, ह. नं. 🗝 🖵	tife. the mail	नहरू संभाग क्र. ४, डभरा 🟋	ালয় 🧸 লগ্ধে মুদ্দবিল

भूमि का नक्शा (प्लान) भू-अर्जन अधिकारी, हसदेव परियोजना, सक्ती के कार्यालय में देखा जा सकता है.

जांजगीर-चांपा, दिनांक 19 अक्टूबर 2005

क्रमांक-क/भू-अर्जन/325.— चूंकि राज्य शासन को यह प्रतीत होता है कि इससे संलग्न अनुसूची के खाने (1) से (4) में वर्णित भूमि की अनुसूची के खाने (6) में उसके सामने दिये गये सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है, अथवा आवश्यकता पड़ने की संभावना है. अत: भू-अर्जन अधिनियम, 1894 (क्रमांक सन् 1894) संशोधित भू-अर्जन अधिनियम, 1984 की धारा 4 की उपधारा (1) के उपबन्धों के अनुसार सभी संबंधित व्यक्तियों को इसके द्वारा इस आशय की सूचना दो जाती है कि राज्य शासन, इसके द्वारा, अनुसूची के खाने (5) में उल्लेखित अधिकारी को उक्त भृमि के संबंध में उक्त धारा 4 की उपधारा (2) द्वारा दी गई शक्तियों का प्रयोग करने के लिए प्राधिकृत करता है. राज्य शासन यह भी निर्देश देता है कि उक्त अधिनियम की धारा 5 (अ) के उपबंध, उक्त भूमि के संबंध में लागू नहीं होंगे, क्योंकि उसकी राय में उक्त अधिनियम की धारा 17 की उपधारा (1) के उपबंध उसके संबंध में लागू होते हैं :—

अनुसूची

भूमि का वर्णन				धारा 4 की उपधारा (2)	सार्वजनिक प्रयोजन
. जिला	तहसील '	नगर∕ग्राम •	लगभग क्षेत्रफल (हेक्टेयर में)	के द्वारा प्राधिकृत अधिकारी	का वर्णन
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
जांजगीर-चांपा	डभरा	कोटमी प. हं. नं. 17	0.412	कार्यपालन यंत्री, मिनीमाता बांगो नहर संभाग क्र. 4, डभरा.	रेड़ा माइनर ७ आर एवं ७ आर/१ आर.

क्रमांक-क/भू-अर्जन/326. —चूंकि राज्य शासन को यह प्रतीत होता है कि इससे सलग्न अनुसूची के खाने (1) से (4) में वर्णित भूमि की अनुसूची के खाने (6) में उसके सामने दिये गये सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है, अथवा आवश्यकता पड़ने की संभावना है. अत: भू अर्जन अधिनियम, 1894 (क्रमांक सन् 1894) संशोधित भू-अर्जन अधिनियम, 1984 की धारा 4 की उपधारा (1) के उपबन्धों के अनुमार सभी संविधत व्यक्तियों को इसके द्वारा इस आशय की सूचना दी जाती है कि राज्य शासन, इसके द्वारा, अनुसूची के खाने (5) में उल्लेखित अधिकारी को उक्त भूमि के संबंध में उक्त धारा 4 की उपधारा (2) द्वारा दी गई शक्तियों का प्रयोग करने के लिए प्राधिकृत करता है. राज्य शासन यह भी निर्देश देता है कि उक्त अधिनियम की धारा 5 (अ) के उपबंध, उक्त भूमि के संबंध में लागू नहीं होंगे, क्योंकि उसकी राय में उक्त अधिनियम की धारा 17 की उपधारा (1) के उपबंध उसके संबंध में लागू होते हैं :—

अनुसूची

		भूमि का वर्णन	;	धारा ४ की उपधारा (2)	सार्वजनिक प्रयोजन
जिला	तहसील	्नगर∕ग्राम	लगभग क्षेत्रफल (हेक्टेयर में)	के द्वारा प्राधिकृत अधिकारो	का वर्णन
· (1)	(2)	(3)	(4)	(5)	. (6)
जांजगीर-चांपा	डभरा	कटेकोनी छोटे _{न ए}		कार्यपालन यंत्रो, मिनीमाता बांगो नहर संभाग क्र. 4, डभरा.	गोवरा सब डीवाय

मूंग का नक्शा (प्लान) भू-अर्जन अधिकारी, हसदेव परियोजना, सक्ती के कार्यालय में देखा जा सकता है.

जांजगीर-चांपा, दिनांक 19 अक्टूबर 2005

क्रमांक-क/भू-अर्जन/327.—चूंकि राज्य शासन को यह प्रतीत होता है कि इससे संलग्न अनुसूची के खाने (1) से (4) में वर्णित भूमि की अनुसूची के खाने (6) में उसके सामने दिये गये सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है, अथवा आवश्यकता पड़ने की संभावना है. अतः भू-अर्जन अधिनियम, 1894 (क्रमांक सन् 1894) संशोधित भू-अर्जन अधिनियम, 1984 की धारा 4 की उपधारा (1) के उपबन्धों के अनुसार सभी संविधित व्यक्तियों को इसके द्वारा इस आशय की सूचना दी जाती है कि राज्य शासन, इसके द्वारा, अनुसूची के खाने (5) में उद्घेखित अधिकारी को उक्त भृमि के संबंध में उक्त धारा 4 की उपधारा (2) द्वारा दी गई शक्तियों का प्रयोग करने के लिए प्राधिकृत करता है. राज्य शासन यह भी निर्देश दंता है कि उक्त अधिनियम की धारा 5 (अ) के उपबंध, उक्त भूमि के संबंध में लागू नहीं होंगे, क्योंकि उसकी राय में उक्त अधिनियम की धारा 17 की उपधारा (1) के उपबंध उसके संबंध में लागू होते हैं:—

अनुसूची

,	भू	में का वर्णन		. धारा ४ की उपधारा (2)	ै सार्वजनिक प्रयोजन
٠.	जिला तहसील	नगर/ग्राम	लगभग क्षेत्रफल	ैं के द्वारा	का वर्णन
			• (हेक्टेयर में)	प्राधिकृत अधिकारी	
•	(1) (2)	(3)	(4)	(5)	(6)
्रार जां	ज्यार-चांपा मालखरौदा -	सपिया	0.024	कार्यपालन यंत्री, मिनीमाता वांगो	संपिया माइनर
''\ ,		والمرافيق والم		नहर संभाग क्र. 4, डभरा.	

क्रमांक-क/भू-अर्जन/328.—चूंकि राज्य शासन को यह प्रतीत होता है कि इससे संलग्न अनुसूची के खाने (1) से (4) में वर्णित भूमि का अनुसूची के खाने (6) में उसके सामने दिये गये सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है, अथवा आवश्यकता पड़ने को संभावना है. अतः भू- अर्जन अधिनियम, 1894 (क्रमांक सन् 1894) संशोधित भू-अर्जन अधिनियम, 1984 की धारा 4 की उपधारा (1) के उपबन्धों के अनुसार सभी संबंधित व्यक्तियों को इसके द्वारा इस आशय की सूचना दी जाती है कि राज्य शासन, इसके द्वारा, अनुसूची के खाने (5) में उल्लेखित अधिकारी को उक्त भूमि के संबंध में उक्त धारा 4 की उपधारा (2) द्वारा दी गई शक्तियों का प्रयोग करने के लिए प्राधिकृत करता है. राज्य शासन यह भी निर्देश देता है कि उक्त अधिनियम की धारा 5 (अ) के उपबंध, उक्त भूमि के संबंध में लागू नहीं होंगे, क्योंकि उसकी राय में उक्त अधिनियम की धारा 17 की उपधारा (1) के उपबंध उसके संबंध में लागू होते हैं :—

अनुसूची

	9	नूमि का वर्णन		धारा 4 की उपधारा (2)	सार्वजनिक प्रयोजन
जिला	तहसील	नंगर∕ग्राम	लगभग क्षेत्रफल (हेक्टेयर में)	के द्वारा प्राधिकृत अधिकारी	का वर्णन
(1)	(2)	(3)	(4)	. (5)	(6)
जांजगीर-चांपा	्रह्म रा १८३८ १८	बांधापाली : , , , ,	*0.081	कार्यपालन यंत्री, मिनीमाता वांगो नहर संभाग क्र. ४, डभरो:	देवरघटा माइनर अमर्ड अफ आफ अ

भूमि का नक्शा (प्लान) भू-अर्जन अधिकारी, हसदेव परियोजना, सक्ती के कार्यालय में देखा जा सकता है.

जांजगीर-चांपा, दिनांक 19 अक्टूबर 2005

क्रमांक-क/भू-अर्जन/329.—चूंकि राज्य शासन को यह प्रतीत होता है कि इससे संलग्न अनुसूची के खाने (1) से (4) में वर्णित भूमि की अनुसूची के खाने (6) में उसके सामने दिये गये सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है, अथवा आवश्यकता पड़ने की संभावना है. अत: भू अर्जन अधिनियम, 1894 (क्रमांक सन् 1894) संशोधित भू-अर्जन अधिनियम, 1984 की धारा 4 की उपधारा (1) के उपबन्धों के अनुसार सभी संबंधित व्यक्तियों को इसके द्वारा इस आशय की सूचना दी जाती है कि राज्य शासन, इसके द्वारा, अनुसूची के खाने (5) में उल्लेखित अधिकारी को उक्त भूमि के संबंध में उक्त धारा 4 की उपधारा (2) द्वारा दी गई शक्तियों का प्रयोग करने के लिए प्राधिकृत करता है. राज्य शासन यह भी निर्देश देता है कि उक्त अधिनियम की धारा 5 (अ) के उपबंध, उक्त भूमि के संबंध में लागू नहीं होंगे, क्योंकि उसकी राय में उक्त अधिनियम को धारा 17 की उपधारा (1) के उपबंध उसके संबंध में लागू होते हैं:—

अनुसूची

	. મુ	्मि का वर्णन		धारा ४ को उपधारा (2)	सार्वजनिक प्रयोजन
जिला	तहसील	नगर∕ग्राम्	लगभग क्षेत्रफल (हेक्टेयर में)	के द्वारा : प्राधिकृत अधिकारी .	का वर्णन
(1)	(2)	(3)	(4)	·(5)	(6)
जांजगीर-चांपा	मालखरौदा	किरारी	0.085	कार्यपालन यंत्री, मिनीमाता वांगो नहर संभाग क्र. 4, डभरा.	ः किरारी टेल माइनर

क्रमांक-क/भू-अर्जन/330. — चूंकि राज्य शासन को यह प्रतीत होता है कि इससे संलग्न अनुसूची के खाने (1) से (4) में विणंत भूमि की अनुसूची के खाने (6) में उसके सामने दिये गये सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है, अथवा आवश्यकता पड़ने की संभावना है. अत: भू अर्जन अधिनियम 1894 (क्रमांक सन् 1894) संशोधित भू-अर्जन अधिनियम, 1984 की धारा 4 की उपधारा (1) के उपवन्धों के अनुसार सभी संबंधित व्यक्तियों को इसके द्वारा इस आशय को सूचना दी जाती है कि राज्य शासन, इसके द्वारा, अनुसूची के खाने (5) में उल्लेखित अधिकारों को उक्त भूमि के संबंध में उक्त धारा 4 की उपधारा (2) द्वारा दी गई शक्तियों का प्रयोग करने के लिए प्राधिकृत करता है. राज्य शासन यह भी निर्देश देता है कि उक्त अधिनियम की धारा 5 (3) के उपबंध, उक्त भूमि के संबंध में लागू नहीं होंगे, क्योंकि उसकी राय में उक्त अधिनियम की धारा 17 की उपधारा (1) के उपवंध उसके संबंध में लागू होते हैं :—

अनुसूची

		भूमि का वर्णन		ं धारा ४ की उपधारा (2)	सार्वजनिक प्रयोजन
जिला	तहसील	नगर/ग्राम	लगभग क्षेत्रफल (हेक्टेयर में)	के द्वारा प्राधिकृत अधिकारी	- कावर्णन .
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
ंजांजगीर- चांपा	्डभरा	केनापाली	0.145	कार्यपालनं यंत्रो, मिनीमाता बांगो	भुरकोट उप वितरक नहर
SETTE:	WHI.	भाक्ष व स्थान	. 🕉 न्नाप्तः "	नहर संभाग क्र. ४, डभरा. 🗥 🗥	मान्य सम्बद्धाः

भूमि का नक्शा (प्लान) भू-अर्जन अधिकारी, हसदेव परियोजना, सक्ती के कार्यालय में देखा जा सकता है.

जांजगीर-चांपा, दिनांक 19 अक्टूबर 2005

क्रमांक-क/भू-अर्जन/331.—चूंकि राज्य शासन को यह प्रतीत होता है कि इससे संलग्न अनुसूची के खाने (1) से (4) में वर्णित भूमि की अनुसूची के खाने (6) में उसके सामने दिये गये सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है, अथवा आवश्यकता एड़ने की संभावना है. अत: भू- अर्जन अधिनियम, 1894 (क्रमांक सन् 1894) संशोधित भू-अर्जन अधिनियम, 1984 की धारा 4 की उपधारा (1) के उपबन्धों के अनुसार सभी संयंधित व्यक्तियों को इसके द्वारा इस आशय की सूचना दी जाती है कि राज्य शासन, इसके द्वारा, अनुसूची के खाने (5) में उल्लेखित अधिकारी को उक्त भूमि के संबंध में उक्त धारा 4 की उपधारा (2) द्वारा दी गई शक्तियों का प्रयोग करने के लिए प्राधिकृत करता है. राज्य शासन यह भी निर्देश देता है कि उक्त अधिनियम की धारा 5 (अ) के उपबंध, उक्त भूमि के संबंध में लागू नहीं होंगे, क्योंकि उसकी राय में उक्त अधिनियम की धारा 17 की उपधारा (1) के उपबंध उसके संबंध में लागू होते हैं :—

अनुसूची

भूमि का वर्णन	धारा 4 की उपधारा (2)	सार्वजनिकःप्रयोजन
जिला तहसील नगर/ग्राम लगभग क्षेत्रफल * (हेक्टेयर में)	के द्वारा	का वर्णन
(1) - (2) (3) (4)	प्राधिकृत अधिकारी ् (5)	, (6)
जांजगीर-चांपा मालखरीदा भाँटा 0.404	कार्यपालन यंत्री, मिनीमाता बांगो 🐣	े टेल माइनर नहर
	. नहर संभाग क्र. ४, डभरा	•

क्रमांक-क/भू-अर्जन/332.—चूंिक राज्य शासन को यह प्रतीत होता है कि इससे संलग्न अनुसूची के खाने (1) से (4) में वांगत भूमि को अनुसूची के खाने (6) में उसके सामने दिये गये सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है. अश्वा आवश्यकता पड़ने की संभावना है. अत: भू अर्जन अधिनियम, 1994 (क्रमांक सन् 1894) संशोधित भू-अर्जन अधिनियम, 1984 को धारा 4 को उपधारा (1) के उपवन्धों के अनुसार मभी संबंधित व्यक्तियों को इसके द्वारा इस आशय की सूचना दी जाती है कि राज्य शासन, इसके द्वारा, अनुसूची के खाने (5) में उन्हेखित अधिकारों को उक्त भूमि के संबंध में उक्त धारा 4 की उपधारा (2) द्वारा दी गई शक्तियों का प्रयोग करने के लिए प्राधिकृत करता है. राज्य शासन यह भी निर्देश देता है कि उक्त अधिनियम की निर्देश के उपबंध, उक्त भूमि के संबंध में लागू नहीं होंगे, क्योंकि उसकी राय में उक्त अधिनियम की धारा 17 की उपधारा (1) के उपबंध उसके संबंध में लागू होते हैं :—

अनुसूची

ू भूमि का वर्णन				्धारा ४ की उपधारा (2)	सार्वजनिक प्रयोजन
जिला	तहसील	नगर∕ग्राम	लगभग क्षेत्रफल (हेक्टेयर में)	कं द्वारा प्राधिकृत अधिकारी	का वर्णन
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
जांजगीर-चांपा	मालखरौदा	सिंधरा 🤼 .	- 🤝 0.153	कार्यपालन यंत्री, मिनीमाता बांगो नहर संभाग क्र. 4, डभरा.	दलालपाली माइनर

भूमि का नक्शा (प्लान) भू-अर्जन अधिकारी, हसदेव परियोजना, सक्ती के कार्यालय में देखा जा सकता है.

जांजगीर-चांपा, दिनांक 19 अक्टूबर 2005 .

क्रमांक-क/भू-अर्जन/333.—चूंिक राज्य शासन को यह प्रतीत होता है कि इससे संलग्न अनुसूची के खाने (1) से (4) में वर्णित भृमि की अनुसूची के खाने (6) में उसके सामने दिये गये सार्वजिनक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है, अथवा आवश्यकता पड़ने की संभावना है. अत: भू-अर्जन अधिनियम, 1894 (क्रमांक सन् 1894) संशोधित भू-अर्जन अधिनियम, 1984 की धारा 4 की उपधारा (1) के उपबन्धों के अनुसार सभी संबंधित व्यक्तियों को इसके द्वारा इस आशय की सूचना दी जाती है कि राज्य शासन, इसके द्वारा, अनुसूची के खाने (5) में उल्लेखित अधिकारी को उक्त भूमि के संबंध में उक्त धारा 4 की उपधारा (2) द्वारा दी गई शक्तियों का प्रयोग करने के लिए प्राधिकृत करता है. राज्य शासन यह भी निर्देश देता है कि उक्त अधिनियम की धारा 5 (अ) के उपबंध, उक्त भूमि के संबंध में लागू नहीं होंगे, क्योंकि उसकी राय में उक्त अधिनियम की धारा 17 की उपधारा (1) के उपबंध उसके संबंध में लागू होते हैं :—

अनुसूर्ची

		भूमि का वर्णन		धारा ४ की उपधारा (2)	सार्वजनिक प्रयोजन
- जिला	तहसील	नग्रं/ग्राम	लगभग क्षेत्रफल (हेक्टेयर में)	के द्वारा प्राधिकृत अधिकारी	का वर्णन
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6) ·
जांजगीर~चांपा [ं]	डभरा	खैरा	0.229	कार्यपालन यंत्री, मिनीमाता बांगी नहर संभाग क्र. 4, डभरा.	ख़िरा माइनर

क्रमांक-क/भू-अर्जन/334. —चूंकि राज्य शासन को यह प्रतीत होता है कि इससे संलग्न अनुसूची के खाने (1) सं (4) में वर्णित भूमि की अनुसूची के खाने (6) में उसके सामने दिये गये सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है, अथवा आवश्यकता पड़ने की संभावना है. अत: भू- अर्जन अधिनियम, 1894 (क्रमांक सन् 1894) संशोधित भू-अर्जन अधिनियम, 1984 की धारा 4 की उपधारा (1) के उपवन्धों के अनुसार सभी संबंधित व्यक्तियों को इसके द्वारा इस आशय की सूचना दी जाती है कि राज्य शासन, इसके द्वारा, अनुसूची के खाने (5) में उझेखित अधिकारी को उक्त भूमि के संबंध में उक्त धारा 4 की उपधारा (2) द्वारा दी गई शक्तियों का प्रयोग करने के लिए प्राधिकृत करता है. राज्य शासन यह भी निर्देश देता है कि उक्त अधिनियम की धारा 5 (3) के उपबंध, उक्त भूमि के संबंध में लागू नहीं होंगे, क्योंकि उसकी राय में उक्त अधिनियम की धारा 17 की उपधारा (1) के उपबंध उसके संबंध में लागू होते हैं:—

अनुसूची

		भूमि का वर्णन	•	धारा ४ की उपधारा (2)		सार्वजनिक प्रयोजन
जिला	तहसील	नगर∕ग्राम	लगभग क्षेत्रफल (हेक्टेयर में)	के द्वारा प्राधिकृत अधिकारी		का वर्णन
(1)	(2)	(3)	(4)	. (5)		(6)
जांजगीर-चांपा	डभरा	कॉसा	0.193	कार्यपालन यत्री, मिनीमाता बांगो नहर संभाग क्र. 4, डभरा.	٠,	ं काँसा माइनर

भूमि का नक्शा (प्लान) भू-अर्जन अधिकारी, हसदेव परियोजना, सक्ती के कार्यालय में देखा जा सकता है.

जांजगीर-चांपा, दिनांक 19 अक्टूबर 2005

क्रमांक-क/भू-अर्जन/335.—चूंकि राज्य शासन को यह प्रतीत होता है कि इससे संलग्न अनुसूची के खाने (1) से (4) में वर्णित भूमि का अनुसूची के खाने (6) में उसके सामने दिये गये सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है, अथवा आवश्यकता एड़ने की संभावना है. अत: भृ-अर्जन अधिनियम, 1894 (क्रमांक सन् 1894) संशोधित भू-अर्जन अधिनियम, 1984 की धारा 4 की उपधारा (1) के उपबन्धों के अनुसार सभी संवधित व्यक्तियों को इसके द्वारा इस आशय की सूचना दीं जाती है कि राज्य शासन, इसके द्वारा, अनुसूची के खाने (5) में उल्लेखित अधिकारी का उक्त भूमि के संबंध में उक्त धारा 4 की उपधारा (2) द्वारा दी गई शक्तियों का प्रयोग करने के लिए प्राधिकृत करता है. राज्य शासन यह भी निर्देश देता है कि उक्त अधिनियम की धारा 5 (अ) के उपबंध, उक्त भूमि के संबंध में लागू नहीं होंगे, क्योंकि उसकी राय में उक्त अधिनियम की धारा 17 की उपधारा (1) के उपबंध उसके संबंध में लागू होते हैं :—

- भूमि का वर्णन	धारा ४ की उपधारा (2) सार्वजनिक प्रयोज	न
जिला तहसील नगर∕ग्राम ल	लगभग क्षेत्रफल के द्वारा का वर्णन	
((हेक्टेयर में) प्राधिकृत अधिकारी	
(2)	(4) (5)	
जांजगीर-चापा मालखराँदा दलालपाली 👅	0.165 कार्यपालन यंत्री, मिनीमाता बांगो दलालपाली माइनर	ŗ
	नहर संभाग क्र. 4, डभरा.	

भूमि की नक्शा (प्लान) भू-अर्जन अधिकारी, हसदेव परियोजना, सूक्ती के कार्यालय में देखा जा सकता है.

क्रमांक-क/भू-अर्जन/336.—'चूंकि राज्य शासन को यह प्रतीत होता है कि इससे संलग्न अनुसूची के खाने (1) स (4) में वर्णित भूमि की अनुसूची के खाने (6) में उसके सामने दिये गये सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है, अथवा आवश्यकता पड़ने की संभावना है. अत: भू-अर्जन अधिनियम, 1894 (क्रमांक सन् 1894) संशोधित भू-अर्जन अधिनियम, 1984 की धारा 4 की उपधारा (1) के उपबन्धों के अनुसार सभी संबंधित व्यक्तियों को इसके द्वारा इस आशय की सूचना दी जाती है कि राज्य शासन, इसके द्वारा, अनुसूची के खाने (5) में उल्लेखित अधिकारी को उक्त भूमि के संबंध में उक्त धारा 4 की उपधारा (2) द्वारा दी गई शक्तियों का प्रयोग करने के लिए प्राधिकृत करता है. राज्य शासन यह भी निर्देश देता है कि उक्त अधिनियम की धारा 5 (अ) के उपबंध, उक्त भूमि के संबंध में लागू नहीं होंगे, क्योंकि उसकी राय में उक्त अधिनियम की धारा 17 की उपधारा (1) के उपबंध उसके संबंध में लागू होते हैं:—

	2
अनस	디
-'3''8	. ''

		भृगि का वर्णन		भारा 4 की उपधारा (2)	•	सार्वजनिक प्रयोजन
जिला	तहसील	नगर/ग्राम	लगभग क्षेत्रफल (हेक्टेयर में)	के द्वारा प्राधिकृत अधिकारी		का वर्णन
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)		.(6)
जांजगीर-चांपा	डभरा	गोबस	0.311	कार्यपालन यंत्री, मिनीमाता बांगो नहर संभाग क्र. 4, डभरा.		सिंधरा वितरक

भूमि का नक्शा (प्लान) भू-अर्जन अधिकारी, हसदेव परियोजना, सक्ती के कार्यालय में देखा जा सकता है.

जांजगीर-चांपा, दिनांक 16 नवम्बर 2005

क्रमांक-क/भू-अर्जन/24.—चूंकि राज्य शासन को यह प्रतीत होता है कि उत्तरे संलग्न अनुसूची के खाने (1) से (4) में वर्णित भूमि की अनुसूची के खाने (6) में उसके सामने दिये गयं सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है, अधना आवश्यकता पड़ने की संभावना है. अतः भू-अर्जन अधिनियम, 1894 (क्रमांक सन् 1894) संशोधित भू अर्जन अधिनियम, 1984 को धारा (1) के उपयन्थों के अनुसार सभी संबंधित व्यक्तियों को इसके द्वारा इस आशय की सूचना दी जाती है कि राज्य शासन, इसके द्वारा, अनुसूची के खाने (3) में उद्घेखित अधिकारी को उक्त भूमि के संबंध में उक्त धारा 4 की उपधारा (2) द्वारा दी गई शक्तियों को प्रयोग करने के तिए प्राधिकृत करता है. सज्य शासन यह भी निर्देश देता है कि उक्त अधिनियम की धारा 5 (3) के उपबंध, उक्त भूमि के संबंध में लागू नहीं होंगे, क्योंकि उसकी राय में उक्त अधिनियम की धारा 17 की उपधारा (1) के उपबंध उसके संबंध में लागू होते हैं :—

अनुसूची

	_	भूमिं का वर्णन		धारा ४ की उपधारा (2)	सार्वजनिक प्रयोजन
जिला	तहसील	नगर/ग्राम	लगभग क्षेत्रफल (हेक्टेयर में)	के द्वारा प्राधिकृत अधिकारी .	का वर्णन
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
जांजगीर-चांपा	डभरा	, गांवरा -	0.122	कार्यपालन यंत्री, मिनीमाता बांगो नहर संभाग क्र. ४, डभरा.	चुरतेला माइनर

जांजगीर-चांपा, दिनांक 16 नवम्बर 2005

क्रमांक-क/भू-अर्जन/25. — चूंकि राज्य शासन को यह प्रतीत होता है कि इससे संलग्न अनुसूची के खाने (1) से (4) में वर्णित भूमि की अनुसूची के खाने (6) में उसके सामने दिये गये सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है, अथवा आवश्यकता पड़ने की संभावना है. अत: भू-अर्जन अधिनियम, 1894 (क्रमांक सन् 1894) संशोधित भू-अर्जन अधिनियम, 1984 की धारा 4 की उपधारा (1) के उपवन्धों के अनुसार सभी संबंधित व्यक्तियों को इसके द्वारा इस आशय की सूचना दी जाती है कि राज्य शासन, इसके द्वारा, अनुसूची के खाने (5) में उह्नेखित अधिकारी को उक्त भूमि के संबंध में उक्त धारा 4 की उपधारा (2) द्वारा दी गई शक्तियों का प्रयोग करने के लिए प्राधिकृत करता है. राज्य शासन यह भी निर्देश देता है कि उक्त अधिनियम की धारा 5 (अ) के उपबंध, उक्त भूमि के संबंध में लागू नहीं होंगे, क्योंकि उसकी राय में उक्त अधिनियम की धारा 17 की उपधारा (1) के उपवंध उसके संबंध में लागू होते हैं:—

अनुसूची

		भूमि का वर्णन	,	धारा ४ की उपधारा (2)	सार्वजनिक प्रयोजन
जिला	तहसील	नगर/ग्राम	लगभग क्षेत्रफल (हेक्टेयर में)	के द्वारा प्राधिकृत अधिकारी	का वर्णन
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
जांजगीर-चांपा	डभरा	बाड़ादरहा	0.620	कार्यपालन यंत्री, मिनीमाता बांगो नहर संभाग ऋ. ४, डभरा.	6 एल माइनर

भूमि का नक्शा (प्लान) भू-अर्जन अधिकारी, हसदेव परियोजना, सक्ती के कार्यालय में देखा जा सकता है.

जांजगीर-चांपा, दिनांक 16 नवम्बर 2005

क्रमांक-क/भू-अर्जन/26. — चूंकि राज्य शासन को यह प्रतीत होता है कि इससे संलग्न अनुसूची के खाने (1) से (4) में वर्णित भूमि की अनुसूची के खाने (6) में उसके सामने दिये गये सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है, अथवा आवश्यकता पड़ने की संभावना है. अत: भू-अर्जन अधिनियम, 1894 (क्रमांक सन् 1894) संशोधित भू-अर्जन अधिनियम, 1984 की धारा 4 की उपधारा (1) के उपबन्धों के अनुसार सभी संबंधित व्यक्तियों को इसके द्वारा इस आशय की सूचना दी जाती है कि राज्य शासन, इसके द्वारा, अनुसूची के खाने (5) में उल्लेखित अधिकारी को उक्त भूमि के संबंध में उक्त धारा 4 की उपधारा (2) द्वारा दी गई शक्तियों का प्रयोग करने के लिए प्राधिकृत करता है. राज्य शासन यह भी निर्देश देता है कि उक्त अधिनियम की धारा 5 (अ) के उपबंध, उक्त भूमि के संबंध में लागू नहीं होंगे, क्योंकि उसकी राय में उक्त अधिनियम की धारा 17 की उपधारा (1) के उपवंध उसके संबंध में लागू होते हैं:—

अनुसूची

· भूमि का वर्णन		धारा ४ की उपधारा (2)	सार्वजनिक प्रयोजन
जिला ′ तहसील नुगर∕ग्राम	लगभग क्षेत्रफल (हेक्टेयर में)	के द्वारा प्राधिकृत अधिकारी	का वर्णन
(2)	(8464(4)	प्राथिकृत आयकारा (5)	(6)
जांजगीर-चांपा मालखरौदा े बड़ेसीपत ,	1,243	कार्यपालन यंत्री, मि. बा. नहर.	बड़ेसीपत माइनर
	•	संभाग क्र. ४, डभरा.	•,

जांजगीर-चांपा, दिनांक 21 नवम्बर 2005

क्रमांक-क/भू-अर्जन/28.— चूंकि राज्य शासन को यह प्रतीत होता है कि इससे संलग्न अनुसूची के खाने (1) से (4) में वर्णित भूमि की अनुसूची के खाने (6) में उसके सामने दिये गये सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है, अथवा आवश्यकता पड़ने की संभावना है. अत: भू-अर्जन अधिनियम, 1894 (क्रमांक सन् 1894) संशोधित भू-अर्जन अधिनियम, 1984 की धारा 4 की उपधारा (1) के उपवन्धों के अनुसार सभी संवंधित व्यक्तियों को इसके द्वारा इस आशय की सूचना दी जाती है कि राज्य शासन, इसके द्वारा, अनुसूची के खाने (5) में उल्लेखित अधिकारी को उक्त भूमि के संवंध में उक्त धारा 4 की उपधः (2) द्वारा दी गई शक्तियों का प्रयोग करने के लिए प्राधिकृत करता है. राज्य शासन यह भी निर्देश देता है कि उक्त अधिनियम की धारा 5 (अ) के विशेष उक्त भूमि के संवंध में लागू नहीं होंगे, क्योंकि उसकी राय में उक्त अधिनियम की धारा 17 की उपधारा (1) के उपवंध उसके संबंध में लागू होते हैं:—

अनुसूची

	9	भूमि का वर्णन			धारा ४ की उपधारा (2)	सार्वजनिक प्रयोजन
जिला	तहसील	नगर∕ग्राम		लगभग क्षेत्रफल (हेक्टेयर में)	ं के द्वारा प्राधिकृत अधिकारी	का वर्णन
(1)	(2)	(3)	•	. (4)	(5)	(6)
जांजगीर-चांपा	ं सक्ती	अरजूनी		0.064	कार्यपालन यंत्री, नहर संभाग खरसिया	ं वगदेवा माइनर

भूमि का नक्शा (प्लान) भू-अर्जन अधिकारी, हसदेव परियोजना, सक्ती के कार्यालय में देखा जा सकता है.

छत्तीसगढ़ के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार, सोनमणि बोरा, कलेक्टर एवं पदेन उप-सचिव.

कार्यालय, कलेक्टर, जिला बिलासपुर, छत्तीसगढ़ एवं पदेन उप-सचिव. छत्तीसगढ़ शासन राजस्त्र विभाग

बिलासपुर, दिनांक 1 दिसम्बर 2005

प्र. क. 8/अ-82/04-05.—चूंकि राज्य शासन को इस बात का समाधान हो गया है कि नीचे दी गई अनुसूची के पद (1) में वर्णित भूमि की अनुसूची के पद (2) में उन्नेखित सार्वजनिक प्रयोजन के लिए आवश्यकता है. अत: भू-अर्जन अधिनियम, 1894 (क्रमांक 1 सन् 1894) की धारा 6 के अन्तर्गत इसके द्वारा यह घोषित किया जाता है कि उक्त भूमि की उक्त प्रयोजन के लिए आवश्यकता है:—

अनुसूची

- (1) भूमि का वर्णन-
 - (क) जिला-विलासपुर
 - (ख) तहसील-बिलासपुर
 - (ग) नगर/ग्राम-लखराम
 - (घ) लगभग क्षेत्रफल-0.94 एकड

	खसरा नम्बर 🍐	रकवा
		(एकड् में)
	(1).	. (2)
	1841/1	. 0.30
1841/2		0.01
1841/3		0.01
	1842/1, 2	0.13
18	343/1, 1844/1	0.11
18	343/2, 1844/2	0.11
	1845/1, 2	0.05
	1846	0.22
योग	8	0.94

- (2) सार्वजनिक प्रयोजन जिसके लिए आवश्यकता हैं- पुल पर पहुंच मार्ग निर्माण हेतु.
- (3) भूमि के नक्शे (प्लान) का निरीक्षण अनुविभागीय अधिकारी (राजस्व), बिलासपुर के न्यायालय में किया जा सकता है.

छत्तीसगढ़ के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार, विकासशील, कलेक्टर एवं पदेन उप-सचिव.

कार्यालय, कलेक्टर, जिला जांजगीर-चांपा, छत्तीसगढ़ एवं पदेन उप-सचिव, छत्तीसगढ़ शासन राजस्व विभाग

जांजगीर-चाम्पा, दिनांक 19 अक्टूबर 2005

क्रमांक 291/सा-1/सात.—चूंकि राज्य शासन को इस बात का समाधान हो गया है कि नीचे दी गई अनुसूची के पद (1) में वर्णित भूमि की अनुसूची के पद (2) में उल्लेखित सार्वजनिक प्रयोजन के लिए आवश्यकता है. अत: भू-अर्जन अधिनियम, 1894 (क्रमांक 1 सन् 1894) संशोधित भू-अर्जन अधिनियम, 1984 की धारा 6 के अन्तर्गत इसके द्वारा यह घोषित किया जाता है कि उक्त भूमि की उक्त प्रयोजन के लिए आवश्यकता है:—

अनुसूची

- (1) भूमि का वर्णन-
 - (क) जिला-जांजगीर-चाम्पा (छत्तीसगढ़)
 - (ख) तहसील-सक्ती
 - (ग) नगर/ग्राम-रगजा, प. ह. नं. 6
 - (घ) लगभग क्षेत्रफल-0.194 हेक्टेयर

7	खसरा नम्बर		रकबा
			(हेक्टेयर में)
	(1)		.(2)
	424/1	•	0.085
	424/2	•	0.081
	427		. 0.028
योग	<u></u>		0.194

- (2) सार्वजिनक प्रयोजन जिसके लिए आवश्यकता है- रगजा उप वितरक नहर निर्माण हेतु.
- (3) भूमि का नक्शा (प्लान) का निरीक्षण भू-अर्जन अधिकारी, हसदेव परियोजना, सकी के कार्यालय में किया जा सकता है.

जांजगीर-चाम्पा, दिनांक 19 अक्टूबर 2005

क्रमांक 292/सा-1/सात.—चृंकि राज्य शासन को इस बात का समाधान हो गुया है कि नीचे दो गई अनुसूची के पद (1) में वर्णित भूमि को अनुसूची के पद (2) में उन्हेंखित सार्वजनिक प्रयोजन के लिए आवश्यकता है जतः भू=अर्जन अधिनयम, 1894 (क्रमांक 1 सन् 1894) संशोधित भू-अर्जन अधिनयम, 1984 की धारा 6 के अनीर्गत इसके उद्धारा प्रहें घोषित कियां जाता है कि उक्त भूमि की उक्त प्रयोजन के लिए आवश्यकता है :—

अनुसूची

- (1) भूमि का वर्णन-
 - (क) जिला-जांजगीर-चाम्पा (छत्तीसगढ़)
 - (ख) तहसील-सक्ती
 - (ग) नगर/ग्राम-जुड्गा, प. ह. नं. 4
 - (घ) लगभग क्षेत्रफल-0.040 हेक्टेयर

	खसरा नम्बर	रंकवा (हेक्टेयर में
	(1)	(2)
	351/2	0.020
	351/3	0.020
	•	
योग		 0.040

- (2) सार्वजनिक प्रयोजन जिसके लिए आवश्यकता है खरसिया शाखा नहरं निर्माण हेत्.
- (3) भूमि का नक्शा (प्लान) का निरीक्षण भू-अर्जन अधिकारी, हसदेव परियोजना, सक्ती के कार्यालय में किया जा सकता है.

जांजगीर-चाम्या, दिनांक 19 अक्टूबर 2005

क्रमांक 293/सा-1/सात.—चूंकि राज्य शासन को इस बात का समाधान हो गया है कि नीचे दी गई अनुसूची के पद (1) में वर्णित भूमि की अनुसूची के पद (2) में उल्लेखित सार्वजनिक प्रयोजन के लिए आवश्यकंता है. अतः भू-अर्जन अधिनियमं, 1894 (क्रमांक 1 सन् 1894) संशोधित भू-अर्जन अधिनयम, 1984 की धारा 6 के अन्तर्गत इसके द्वारा यह घोषित किया जाता है कि उक्त भूमि की उक्त प्रयोजन के लिए आवश्यकता है:—

- (1) भूमिं का वर्णन-
 - (क) जिला-जांजगीर-चाम्य (छत्तीसगढ़)
 - _(ख) तहसील-सक्ती
 - (ग) नेगूर/ग्राम-पासीट, <u>प. ह. नं.</u> <u>1</u>2
 - (घ) लगभग क्षेत्रफल ५०.०81 हेक्टेयर

(3	खसंरा नम्बर	•	रकबा . (हेक्टेयर में)
	, (1)		(2)
	552		0.081
योग ं			. 0.081

- (2) सार्वजनिक प्रयोजन जिसके लिए आवश्यकता है- पासीद माइनर नहर निर्माण.
- (3) भूमि का नक्शा (प्लान) का निरीक्षण भू-अर्जन अधिकारी, हसदेव परियोजना, सक्ती के कार्यालय में किया जा सकता है.

छत्तीसगढ़ के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार, सोनमणि बोरा, कलेक्टर एवं पदेन उप-सचिव.

